04 - नाम में क्या रखा है: नारी के अस्तित्व का संघर्ष

05 - महिलाओं की बढ़ती उड़ान और सामने खड़ी चुनौतियाँ

06 - अदालत ने चेक अनादरित मामले में दोषी को सजा-मय ब्याज राशि भुगतान...

07 - फिर लौट आया सिनेमा का स्वर्णिम युग!

A Daily News Magazine

भोपाल

रविवार, 08 मार्च, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 184, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

श्रम और सामर्थ्य

फोटो: गिरीश शर्मा

टी 20 वर्ल्डकप का फाइनल मैच आज

खिताबी भिड़ंत में भारत और न्यूजीलैंड की होगी टक्कर

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग होगी। फाइनल से पहले ही आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 8 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है।

आईसीसी के नोमिनेशन में भारत के संजू सैमसन का भी नाम है। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड 15वीं बार फाइनल खेलने उतरेगी। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में मिली पहली वर्ल्ड कप जीत से शुरू हुआ यह सफर भारत को अब तक 7 ट्रॉफियां दिला चुका है। आईसीसी टूर्नामेंट्स (वनडे वर्ल्ड कप + चैंपियंस ट्रॉफी + टी-20 वर्ल्ड कप + वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप) में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने 14 फाइनल में से 10 ट्रॉफियां जीती हैं। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी का भारत-श्रीलंका फाइनल बारिश के कारण दो दिन में भी पूरा नहीं हो सका था। इसलिए दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया।

हम एकत्व को नहीं पहचानते इसलिए हो रहे हैं आक्रमण

- जैसलमेर में बोले मोहन भागवत, सद्भावना व एकता पर जोर

कहा-हम बंटे हुए हैं, इसलिए चारों तरफ आक्रमण हो रहे हैं

जैसलमेर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने सद्भावना व एकता पर जोर देते हुए कहा कि समय बड़ा कठिन है। हम बंटे हुए हैं, इसलिए चारों तरफ आक्रमण हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी खत्म भी नहीं हुआ था। इसी बीच अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम अपने एकत्व को नहीं पहचानते, इसलिए दुनियाभर में कलह थमती नहीं है और युद्ध चलते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि लोग मन की करुणा भूल गए हैं और इस सत्य को भूल गए कि हम दिखते अलग-अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं। जब हम विविधता को अलगाव की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब मतभेद पैदा होते हैं,

इसलिए विविधता को स्वीकार करते हुए भी अपनी एकता को नहीं भूलना चाहिए। संघ प्रमुख जैसलमेर में जैन समुदाय के चादर महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर धर्म सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहला विश्व युद्ध हुआ, यह फिर से न हो इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लेकिन वह नहीं चली। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। यह फिर से न हो इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। लेकिन अब देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। वह अपनी जगह पर है, निष्प्रभावी है। जो युद्ध चल रहे हैं वे थम नहीं रहे।

भागवत ने कहा कि हम सभी भेद और स्वार्थ को तिलांजलि देकर और देश के लिए जीने-मरने को तैयार हो जाए तो हमारा समाज अच्छा बनेगा। भारत विश्वगुरु बनकर एक सुखी-सुंदर दुनिया को जन्म देगा। हम सभी मूल रूप से समान हैं क्योंकि परमात्मा एक ही है। जब समाज में अनेकता का आभास होने लगता है तो अलगाव की स्थिति पैदा होने में देर नहीं लगती। इसलिए हमें सदैव एकता पर ही ध्यान रखना चाहिए।

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

लेडीज रूमाल
मर्दों के रूमाल से
छोटा होता है -
लगभग आधा !
यह एक तथ्य है
यदि इसे प्रश्न की तरह पूछें तो
क्या आधा होता है स्त्रियों का पसीना
या आँखों से झरने वाली वेदना?
क्या आधी होती हैं
परेशानियाँ औरतों की
या कि संघर्ष पुरुषों की बनिस्बत?
क्या इसलिए छोटा होता है
लेडीज रूमाल ताकि रखकर उसे
कहीं घेरी जा सके अपनी जगह कथित
औकात के मुताबिक़?

अभी-अभी देखा मैंने कि
वही छोटा लेडीज रूमाल
फुसफुसा रहा है
औरत के कान में
औरत ने भींच लिया है रूमाल अपनी
मुट्ठी में निचोड़ रही है रूमाल से
नीर भरी दुःख की बदली झरझर
अब वह औरत सुखायेगी
रूमाल को
और फहरायेगी
उसे हवा में पताका की तरह।

- निरंजन श्रोत्रिय

मप्र में 'क्वींस ऑन द व्हील्स' का आगाज

1400 किमी का सफर और 25 जांबाज महिला राइडर्स, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश की सड़कों पर अब नारी शक्ति के साहस और रोमांच की गूंज सुनाई देगी। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के तीसरे महिला बाइकिंग टूर का शुभारंभ किया। महिला दिवस और रंगपंचमी के उल्लास के बीच शुरू हुआ यह सफर न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि देश को यह संदेश भी देगा कि मध्यप्रदेश महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सुलभ है।

7 दिन, 1400 किलोमीटर और 25 जांबाज राइडर- इस विशेष टूर में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों की 25 अनुभवी महिला बाइक राइडर्स शामिल हैं। यह दल 7 से 13 मार्च तक मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू होगा। मुख्यमंत्री ने राइडर्स से संवाद करते हुए कहा कि यह यात्रा मध्यप्रदेश की बेटियों के लिए अद्वितीय और साहसपूर्ण सिद्ध होगी। देश सुरक्षित है और मध्यप्रदेश भी सुरक्षित है। हमारी ये बहनें मध्यप्रदेश में महिला सुरक्षा की गारंटी के रूप में इस टूर पर निकल रही हैं। निमाड़ की सादगी से लेकर चंबल के गौरवशाली इतिहास तक, वे हमारे प्रदेश की विविधता को दुनिया के सामने रखेंगी।

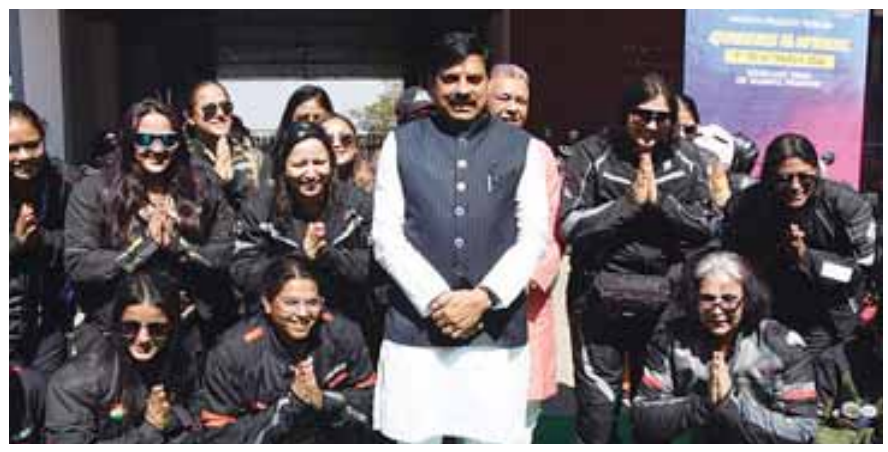

सुरक्षा और संवाद पर जोर

मुख्यमंत्री ने दल में शामिल राइडर्स को एक्सपर्ट बताते हुए उन्हें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। साथ ही, जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि इन महिला राइडर्स के ठहरने और भोजन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में पर्यटन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया, जो इस पूरी यात्रा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचारित करेंगे। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे।

- हो गया है सीक्रेट समझौता! आईआरजी ने अमरीका को दी चेतावनी

चीन के बाद होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की भी आवाजाही शुरू

तेहरान (एजेंसी)। चीन के बाद भारतीय कार्गो जहाज भी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने लगे हैं। ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि भारत के दो कार्गो जहाज पुष्पक और अब परिमल इस व्यापारिक मार्ग से पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने सिर्फ चीन के कार्गो जहाजों को ही इस रास्ते से गुजरने की मंजूरी दी थी लेकिन अब जबकि दो भारतीय जहाज इस रास्ते में हैं तो ऐसा लग रहा है कि भारत और ईरान के बीच कोई समझौता हो गया है या फिर ये दोनों जहाज अपने रिस्क पर इस रास्ते से गुजर रहे हैं।

- **भारत और ईरान के बीच गुपचुप समझौता हुआ!**- भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की उस वक्त बात हुई है जब अमेरिका ने श्रीलंका के पास डेना नाम के युद्धपोत पर हमला कर उसे डुबो दिया। ये जहाज भारतीय नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास के बाद लौट रहा था। इसे ईरान के समुद्र तट से करीब 2,000 मील दूर इंटरनेशनल पानी में बिना किसी पहले चेतावनी के निशाना बनाया गया था। इस हमले के बाद भारत ने हिंद महासाग में फंसे दूसरे जहाजों को शरण देना शुरू कर दिया है। द हिंदू ने दावा किया कि भारत ने एक ईरानी जहाज को कोच्चि में डॉक करने की इजाजत दी है।

आईआरजी ने कहा-कर रहे हैं अमेरिका का इंतजार

होर्मुज स्ट्रेट से उस वक्त भारतीय कार्गो जहाज गुजर रहे हैं जब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि वे यूएस सेना के होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को एस्कॉर्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो इस व्यापारिक मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी को लेकर आईआरजी ने ये नई चेतावनी जारी की है। समाचार एजेंसीकी रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी सलाह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अमेरिकी 1987 में अमेरिकी सुपरटैंकर ब्रिजटन में लगी आग को याद करें। दूसरी तरफ पहले पुष्पक और अब परिमल को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते देखा जा रहा है। इस व्यापारिक मार्ग को फिलहाल 'मौत का मुंह' कहा जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि या तो ईरान के साथ भारत का कोई सीक्रेट समझौता हो गया है या फिर इन दोनों जहाजों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही इन समुद्री रास्तों में जहाजों पर हमले कर रहे हैं ऐसे में हो सकता है कि ईरान ने भारत की मदद की हो।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 25 °c

न्यूनतम 22°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ रविवार, 08 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संत राम रहीम पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में बरी

- हाईकोर्ट ने दिया फैसला,7 साल पहले उम्रकैद हुई थी, 3 अन्य की सजा बरकरार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले 17

जनवरी 2019 को पंचकूला की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी आरोपियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जिस वजह से राम रहीम को बरी कर दिया गया। राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पहले ही हाईकोर्ट से बरी हो चुका है। हालांकि सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण केस में 10 साल कैद की सजा हुई है।

'यात्रा' से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करेंगे निशांत

- पिता नीतिश की तरह ही बनाया प्लान, ब्लू प्रिंट भी तैयार

पटना (एजेंसी)। सीएम नीतिश कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को जेडीयू विधानमंडल दल की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। इस बैठक में तय हो गाया कि निशांत कुमार 8 मार्च को जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। निशांत कुमार इसके बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ अब साफ दिखने लगा है। निशांत कुमार पिता नीतिश कुमार की तरह ही अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करेंगे। याद कीजिए

2005 के फरवरी में हुए चुनावों को जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। सत्ता की चाबी लोजपा के पास थी लेकिन दिवंगत रामविलास पासवान किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़ गए थे। तब नीतिश कुमार ने क्या किया था। पिता नीतिश कुमार की तरह ही निशांत कुमार भी यात्रा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जनता और कार्यकर्ता का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा भी रखा जा सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि निशांत कुमार की यात्रा का नाम क्या होगा।

दुर्भाग्य है कि धर्मयुद्ध के लिए निकलना पड़ रहा

- शंकराचार्य बोले-जिंदा हिंदू लखनऊ चलें लिखे पोस्टर बांटे

वाराणसी (एजेंसी)। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। अपने ही देश में, अपने ही वोट से चुनी सरकार के सामने, अपनी ही गौ-माता को बचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बातें काशी में लखनऊ रवाना होने से पहले शनिवार को कही। शंकराचार्य ने इस आंदोलन को गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा का नाम दिया। वह 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। यहां हजारों संतों

की मौजूदगी में सभा करेंगे। इसमें सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग करेंगे। शंकराचार्य ने 30 जनवरी को योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने तब कहा था- गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। वरना आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य काशी से जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर होते हुए 5 दिन बाद लखनऊ पहुंचेंगे। यात्रा में 20 से अधिक गाड़ियां हैं। 500 से अधिक श्रद्धालु साथ हैं। इस दौरान लोगों को पोस्टर बांटे गए। इनमें लिखा है- जिंदा हिंदू लखनऊ चलें। इससे पहले, शंकराचार्य सुबह 8.30 बजे मठ से निकलकर गौशाला पहुंचे। गाय की पूजा की। फिर पालकी पर सवार हुए।

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड परियोजना किसान और सरकार के बीच विश्वास की बनेगी मिसालः सीएम

3 हजार करोड़ की लागत के बनेगा मार्ग

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड के किसानों के हित में जमीनी स्तर पर मार्ग निर्माण को स्वीकृति और उचित मुआवजे की व्यवस्था किए जाने पर इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र के निवासियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पगड़ी और बड़ी माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास पधारे सभी लोगों को होली और रंगपचमी की बधाई दी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 3 हजार करोड़ रुपए की लागत से इंदौर और उज्जैन के बीच बनने वाली सड़क से इंदौर और उज्जैन का सफर सवा घंटे की जगह आधे घंटे का रह जायेगा। दोनों शहरों के बीच तेज कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्थानीय स्तर पर उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, किसानों को मण्डियों तक पहुंच और व्यापारियों तथा उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह मार्ग, देश के व्यापार व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रो के बीच इस मार्ग से यात्रा सुगम और कम समय में होगी। परिणामस्वरूप आवागमन बढ़ेगा और देश में इंदौर-उज्जैन क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ेगा।

इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में विकास के नए युग का होगा सूत्रपात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पारम्परिक और ऐतिहासिक रूप से इंदौर और उज्जैन के बीच इस मार्ग का ही उचित उपयोग होता था। इस मार्ग से इंदौर के 20 और उज्जैन के 6 गांव लाभान्वित होंगे। सिंहस्थ के लिए भी यह मार्ग सुविधाजनक और उपयोगी होगा। इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में विकास की दृष्टि से नए युग का सूत्रपात हो रहा है। राज्य सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है।

किसानों के हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई के लिये पानी : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। केन-बेतना नदी जोड़ो परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना सहित आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। गत 2 वर्ष में ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा 10 लाख हैक्टेयर बढ़ा है। अब प्रदेश की 55 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। हम अपनी नदियों से राजस्थान और उत्तरप्रदेश को भी पानी उपलब्ध कराते हैं। बिहार और गुजरात को भी पानी मिलता है। पूर्व सरकारों ने नदियों की जलराशि का उचित प्रबंधन करने पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों से विदिशा जिले को भी केन-बेतवा नदी परियोजना का पूरा लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश आज बिजली सरप्लस स्टेट है। अब किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे लिए खेतों में किसान और सीमा पर जवान दोनों बराबर है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं और अंदरूनी इलाके सुरक्षित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विदिशा में प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगर प्रिंट लैब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को शमशाबाद में कृषक हितग्राही सम्मेलन और विकास कार्यों के भूमि-पूजन एवं लोकर्पण कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों को हर साल 12 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में दिए जा रहे हैं। विदिशा जिला कृषि उत्पादन के मामले में अग्रणी है।

पड़ोसी देशों पर अब कोई हमले नहीं करेगा ईरान

राष्ट्रपति पेजेशकियन ने किया वादा, मांगी भी माफी

तेहरान (एजेंसी)। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा कि सैन्य बलों को एक आदेश दिया गया है। अब से, पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें जब तक कि उन पर पहले हमला न हो। जो लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उन्हें साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा है कि अब ईरान उन देशों पर हमला नहीं करेगा। पेजेशकियान ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में कहा,मुझे लगता है कि उन पड़ोसी देशों से माफी मांगना जरूरी है जिन पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा, हमारा पड़ोसी देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। हम शांति और सुकून कायम करने के लिए इलाके में सहयोग की अपील करते हैं। पेजेशकियन ने कहा, सैन्य बलों को एक आदेश दिया गया है। अब से, पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें जब तक कि उन पर पहले हमला न हो।

- **सऊदी अरब ने दी थी ईरान को चेतावनी-** इससे पहले, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने देश के सैन्य ठिकानों और तेल केंद्रों पर हुए सिलसिलेवार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ईरान को गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने की कड़ी चेतावनी दी थी। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी वाले एक एयर बेस और एक प्रमुख तेल क्षेत्र को निशाना बनाकर किये गये हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, राजधानी रियाद के दक्षिण-पूर्व स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस की ओर दागी गयी एक बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से पुष्टि की है कि इसी एयर बेस पर एक और मिसाइल हमला हुआ, जिसे भी विफल कर दिया गया।

संकट में भारत को मिला ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का साथ

भारत में अतिरिक्त गैस सप्लाई के लिए बढ़ा दिया अपना हाथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इससे भारत समेत कई देशों को क्रूड ऑयल और गैस की दिक्कत हो सकती है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई देशों ने भारत को अतिरिक्त गैस सप्लाई की पेशकश की है। सूत्रों ने कहा मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति अब किसी एक समुद्री मार्ग पर निर्भर नहीं है। एक ही समुद्री मार्ग पर निर्भरता के दिन अब लद चुके हैं। भारत जितना तेल आयात करता है, उसका करीब आधा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। बाकी का क्रूड ऑयल अन्य मार्गों से आता है, जो अभी प्रभावित नहीं हैं।

अमेरिका और यूएई के साथ नए समझौते

भारत ने हाल ही में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे साझेदार देशों के साथ भी नई ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थाएं की हैं। इसका मकसद है कि लंबी अवधि के लिए स्थिर सप्लाई सुनिश्चित हो सके। पिछले दस वर्षों में भारत ने अपनी तेल आपूर्ति के स्रोत 27 देशों से बढ़ाकर 40 देशों तक कर दिए हैं, जो छह महाद्वीपों में फैले हुए हैं। वैश्विक संकट के कारण पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल की कीमत करीब 15 फीसदी बढ़ गई है। इसके बावजूद भारत में ईंधन कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल कीमतें लगभग 55 फीसदी बढ़ गई हैं। वहीं जर्मनी में 22,फ्रांस में 19 फीसदी और अमेरिका में 11 फीसदी से ज्यादा उछाल आया है।

अब भारत बनेगा राफेल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब

फ्रांस के बाहर बड़ी उपलब्धि, डसॉल्ट ने बताया प्लान

पेरिस (एजेंसी)। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने पुष्टि कर दी है कि फ्रांस के बाहर प्रोडक्शन लाइन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा डसॉल्ट ने कहा है कि राफेल फाइटर की प्रोडक्शन क्षमता को भी साल 2029 तक हर महीने बढाकर 4 करने का लक्ष्य रखा गया है। डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने 4 मार्च को कहा है कि वह धीरे-धीरे राफेल फाइटर का प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि 2029 तक हर महीने चार राफेल बनाने का लक्ष्य है लेकिन उसे बढ़ाकर पांच करने पर भी विचार चल रहा है। पिछले कुछ सालों में यह बढ़ोतरी एक्सपोर्ट सेल्स को सपोर्ट कर रही है, और कंपनी को और ऑर्डर पूरे करने के लिए तैयार कर रही है। इस बीच, डसॉल्ट देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में फाइटर की बड़ी सब-असेंबली बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चूंकि एयरफ्रेमर दक्षिण एशियाई देश के साथ एक और बड़े कॉन्ट्रैक्ट की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वह और भी ज्यादा लोकल प्रोडक्शन के लिए तैयारी कर रहा है।

लोग केरल स्टोरी-2 नहीं देख रहे, ये अच्छी खबर

राहुल बोले-फिल्मों और मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा के लिए हो रहा

इडुक्की (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि फिल्म केरल स्टोरी-2 गोज बियॉन्ड को ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं और यह अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि फिल्मों, टीवी और मीडिया का इस्तेमाल तेजी से प्रोपेगैंडा के रूप में किया जा रहा है। केरल में इडुक्की के कुट्टिकनम स्थित मैरियन कॉलेज में शुक्रवार को छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की। एक छात्र ने फिल्मों के प्रोपेगैंडा के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर

सवाल पूछा था। इस पर गांधी ने कहा- अच्छी खबर यह है कि केरल स्टोरी खोखली लगती है और लोग इसे देखने नहीं जा रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि बहुत से लोग केरल और उसकी परंपराओं व संस्कृति को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कहा कि आज फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया को तेजी से नफरत फैलाने का हथियार बनाया जा रहा है। इनका इस्तेमाल लोगों को बदनाम करने, उन्हें खत्म करने और समाज में फूट डालने के लिए किया जाता है, ताकि कुछ लोगों को फायदा हो और दूसरों को नुकसान हो। **यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े लोग-** देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक खास विचारधारा का दबाव बढ़ रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर देखें तो उनमें से कई की नियुक्ति इसलिए हुई है क्योंकि वे आरएसएस या किसी खास विचारधारा से जुड़े हैं। शिक्षा को किसी एक सोच तक सीमित नहीं होना चाहिए। भारत अभी अमेरिका और चीन के स्तर तक नहीं पहुंचा है। यदि भारत एआई के क्षेत्र में मजबूत बनना चाहता है, तो उसे अपने डेटा पर नियंत्रण रखना होगा। अमेरिका को वैश्विक डेटा तक व्यापक पहुंच है, जबकि चीन अपना डेटा खुद नियंत्रित करता है, जिससे एआई में उसकी स्थिति मजबूत होती है। ऊपर से देखने पर वेस्ट एशिया में चल रहा तनाव अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान का संघर्ष लगता है, लेकिन बड़े जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी उलझेंगे।

राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का समीकरण बिगाड़ेगी भाजपा

- बनाया बड़ा प्लान, कांग्रेस को फिर लग सकता है तगड़ा झटका

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा की दस राज्यों की 37 सीटों में केवल तीन राज्यों की 11 सीटों के लिए ही मतदान होगा। इनमें बिहार की पांच, ओडिशा की चार एवं हरियाणा की दो सीट शामिल हैं। अन्य राज्यों में निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है। इस बीच भाजपा ने ओडिशा में बीजू जनता दल और हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं, बिहार में राजद और एनडीए में एक सीट के लिए कड़ा मुकाबला हो सकता है। ओडिशा में भाजपा दो और बीजद एक सीट जीत सकती है, लेकिन चौथी सीट पर भाजपा समर्थित निर्दलीय दिलीप राय और बीजद के दत्तेश्वर होता में सीधा मुकाबला है। जीत के लिए 30 वोट चाहिए। भाजपा के पास अपने 79 और तीन निर्दलीय का समर्थन है। यानी तीसरे प्रत्याशी के लिए 22 वोट बचे हैं। ऐसे में दिलीप रे के लिए आठ वोट और चाहिए। वहीं बीजद के 48 विधायक हैं उसे दूसरी सीट के लिए 12 वोट चाहिए।

भारत में छात्रों का 'लोन वुल्फ' नेटवर्क बनाने का प्लान

देश में जैश-ए-मोहम्मद की साजिश का हो गया भंडाफोड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन ने एक मेडिकल संस्थान में घुसपैठ कर डॉक्टरों को भारत में हमले करने के लिए अपने साथ जोड़ लिया था। जांच एजेंसियों के अनुसार इस व्हाइट-कॉलर मॉड्यूल ने करीब 2500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जुटा लिया था और दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई हमले करने की योजना बनाई थी। खुफिया एजेंसियों को अब एक और साजिश का पता चला है, जिसमें जैश ए मोहम्मद स्कूलों और कॉलेजों में घुसपैठ कर छात्रों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने की योजना बना रहा था। आतंकी संगठन अपने प्रचार सामग्री के जरिए कुछ छात्रों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वे अपने दोस्तों के बीच भी उसकी

विचारधारा फैलाएं। एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों को शामिल करने की यह रणनीति दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। ऐसी रणनीति पहले जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की ओर से पाकिस्तान में अपनाई जा चुकी है और अब इसे भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, कम उम्र में छात्रों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने से इन संगठनों को लंबे समय में फायदा होता है। जब ये छात्र 20-25 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वे इतने कट्टर बन चुके होते हैं कि देशभर में हमले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस ने इस सप्ताह मुंबई से एक छात्र को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अयान शेख के रूप में हुई है।

धीरे-धीरे युवाओं को जोड़ रहा था ये संगठन

अधिकारियों के अनुसार संगठन जल्दबाजी में बड़ी संख्या में भर्ती नहीं करना चाहता, बल्कि अगले 5 से 10 वर्षों की योजना बनाकर धीरे-धीरे युवाओं को जोड़ रहा है, ताकि समय-समय पर हमले करने के लिए उसके पास पर्याप्त लोग मौजूद रहें। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस योजना में बड़े मॉड्यूल बनाने के बजाय 'लोन वुल्फ' या दो लोगों की छोटी टीम पर जोर दिया जा रहा है।

फरीदाबाद मॉड्यूल से साजिश का खुलासा

फरीदाबाद मामले से संगठन ने यह सीखा कि बड़े मॉड्यूल में ज्यादा लोगों के शामिल होने से संचार ट्रैक होने का खतरा बढ़ जाता है और मॉड्यूल का पर्दाफाश हो सकता है। इसलिए छात्र मॉड्यूल में हमलावरों को अकेले या 'बडी पेयर' के रूप में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा।

इंदौर में पारा 36डिग्री, भोपाल-ग्वालियर में 35 डिग्री पार

एमपी में तेज धूप से गर्मी बढ़ी ; दोपहर में 3 घंटे छांव में रहने की सलाह

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मार्च के दूसरे पखवाड़े में तेज गर्मी का ट्रेंड है। पिछले 10 साल में 15 मार्च के बाद ही तेज गर्मी पड़ी है, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल गया है। दूसरे पखवाड़े की बजाय शुरुआत में ही पारे में उछाल आया है। सागर, ग्वालियर-चंबल के बाद इंदौर और उज्जैन संभाग में भी गर्मी बढ़ गई है।

इंदौर में पारा 36.2 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में 35 डिग्री के पार है। शुक्रवार को नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री दर्ज किया गया। धार, दमोह, सागर, शाजापुर, गुना, छतरपुर, रतलाम और टीकमगढ़ में तापमान 36 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। वहीं, रात में तापमान 18 डिग्री से ज्यादा है।

आसमान साफ, तेज धूप से बढ़ा गर्मी का असर- मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्से से एक टर्फ गुजर रही है। वहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) भी एक्टिव है, लेकिन प्रदेश में ज्यादा असर नहीं है। आसमान साफ होने की वजह से सूरज की तेज धूप सीधे जमीन पर आ रही है। जिससे गर्मी का असर बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को अर्पित की विनम्र श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत रत्न, स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्र के लिए श्रद्धेय गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिबद्धता और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए देशवासी सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

सीएम डॉ. यादव ने दी जन औषधि दिवस की शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को जन औषधि दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी के उत्तम स्वास्थ्य और निरोग जीवन के लिए जन औषधि केंद्र की सौगात दी है। इन केंद्रो पर उपलब्ध हो रही रियायती दरों पर दवाई से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का बेहतर इलाज सुनिश्चित हो रहा है। भारत सरकार की यह पहल देशवासियों के लिए वरदान के समान है।

मुख्यमंत्री ने स्वामी परमहंस योगानंद पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान आध्यात्मिक गुरु, स्वामी परमहंस योगानंद की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामी जी ने योग व ध्यान के निरोग के संदेश से विश्व को आरोग्य के आलोक से प्रकाशित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उनके द्वारा मार्ग के आधार पर मानव कल्याण के पावन ध्येय की प्राप्ति के लिए दिखया गया मार्ग सभी का कल्याण कर रहा है।

भोपाल में गोमांस से भरे कंटेनर मामले में चालान पेश

एसआईटी के चालान में भी मांस गाय का होने की पुष्टि, 56 दिन बाद गुपचुप तरीके से पेश किया

भोपाल (नप्र)। भोपाल में पुलिस मुख्यालय के सामने गोमांस से भरे कंटेनर पकड़ाने के मामले में एसआईटी ने चालान पेश कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के 56 दिन बाद गुरुवार को गुपचुप तरीके से चालान पेश किया गया। एसआईटी की जांच में भी मांस गाय का ही होने की पुष्टि हुई है।

दरअसल, 17 दिसंबर 2025 को गोमांस से भरा कंटेनर मिला था। जिसमें 26 टन से अधिक गोमांस अलग-अलग पैकेट में भरा था। मांस से भरे कंटेनर को जय मां भवानी हिंदू संगठन के प्रमुख भानू हिंदू और उनकी टीम ने पकड़ा था। मांस की सैम्पलिंग मथुरा की लैब में कराई गई। 5 जनवरी को आई

सैंपल रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया था। इस रिपोर्ट में मांस गाय का ही होने की पुष्टि हुई थी। यह मांस भोपाल के जिंसी स्थित नगर निगम के स्लॉटर हाउस से निकला था। जिसका संचालन असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा करता था। 7 जनवरी को असलम और कंटेनर के ड्राइवर शोएब की गिरफ्तारी की गई थी।

265 क्विंटल मांस से 5 डिब्बों में लिए सैंपल- चालान के मुताबिक कंटेनर को रोककर जांच के दौरान पैकेट में मांस मिला था। जहांगीराबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी मान सिंह चौधरी ने एफआईआर दर्ज की। 17 दिसंबर को कंटेनर नंबर यूपी 15 जेटी 4286 में मांस मिलने का हवाला दिया है।

18 दिसंबर को वेटनरी अस्पताल जहांगीराबाद में कंटेनर में भरे 265 क्विंटल (26.5 टन) मांस में से वेटनरी डॉक्टर की टीम ने अलग-अलग 5 डिब्बों में सैंपल लिए। बाकी मांस कंटेनर के ड्राइवर शोएब पिता कमालउद्दीन को ही सुपुर्दगी में दे दिया गया। पुलिस ने जो सैंपल कंटेनर में मिले मांस के लिए थे, उन्हें पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी मथुरा को भेजे। संदिग्ध मांस के सैंपल की जांच रिपोर्ट भी मिल गई।

देर रात सीएम हाउस पहुँचे विधायक कालूहेड़ा

सीएम-प्रदेशाध्यक्ष की समझाइश के बाद बोले: अब सिंहस्थ के कामों में सहयोगी रहूंगा

भोपाल (नप्र)। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में आंदोलन की धमकी देने वाले उज्जैन उत्तर के बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेडा को भोपाल तलब किया गया। शुक्रवार देर रात वे भोपाल में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह से मिले। इसके बाद फिर वे सीएम हाउस पहुंचे। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी डॉ महेन्द्र सिंह ने विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा को सिंहस्थ के लिए बनने वाली रोड़ के मामले में दिए गए वक्तव्यों के लिए नाराजगी जाहिर की।

विधायक बोले- अब सिंहस्थ के कामों में सहयोगी रहूंगा- सीएम और संगठन की समझाइश के बाद कालूहेडा ने अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि वे अब आगे सिंहस्थ के कामों में सहयोगी बनेंगे। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आम जनता से प्रशासनिक अधिकारी चर्चा करके निर्णय लें।

उज्जैन के पिपलीनाका में सड़क चौड़ीकरण बना विवाद

दरअसल, उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि पिपलीनाका क्षेत्र की सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो वह रोड पर उतरेंगे। सड़क चौड़ीकरण से कई परिवारों की रोजी-रोटी में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अधिकारियों ने सीएम को गलत जानकारी दी। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि मैंने क्षेत्रवासियों को वचन दिया। 24 मीटर की ही रोड होगी, नहीं तो आपका विधायक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जन आंदोलन करेंगे। मैं उसका नेतृत्व करूंगा। कलेक्टर से बोला है कि आप सीएम से बात करें।

7 दिन में खाली करने का नोटिस

जानकारी के मुताबिक भैरव गढ़ रोड के किनारे करीब 410 घर हैं। इनमें से कई बच्चों के बोर्ड एग्जाम हैं। ऐसे में नगर निगम ने 7 दिन में घर खाली करने का नोटिस जारी किया। नोटिस के मुताबिक कई घरों का हिस्सा 10 फीट का तो कुछ का 20 फीट तक ही बच रहा है। बाकी को बुलडोजर से तोड़ने की तैयारी है।

नोटिस मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। विधायक अनिल जैन के कार्यालय को घेर लिया। सरकार और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक की गाड़ी के सामने बैठे और उनके सामने प्रदर्शन किया। विधायक ने वादा किया कि 24 मीटर से ज्यादा चौड़ी होने पर वह खुद सड़क पर उतरेंगे।

विधायक बोले- मैं जनता की भावना का सम्मान नहीं कर पा रहा

स्थानीय लोगों को समझाने के बाद विधायक ने कहा, मैंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि पब्लिक की भावना का सम्मान नहीं कर पा रहा हूं। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में छोटी-छोटी बातों को तूल देना ठीक नहीं है। कुछ बातें इतनी सीरियस होती हैं कि अधिकारी चीफ मिनिस्टर को बता देते हैं। गलत जानकारी भी देते हैं।

कैलाश विजयवर्गीय का तंज

आजकल चार लोग पीछे आ जाएं तो कॉलर खड़ी हो जाती है , संत नागर की सादगी पर हुए कायल

इंदौर (नप्र)। कथावाचक संत कमल किशोर नागर की कथा के दौरान प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मंच से संत कमल किशोर नागर की प्रशंसा करते हुए कहा कि मालवा की धरती सच में धन्य है, जहां इतने बड़े संत निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि संत कमल किशोर नागर ने अपनी ओजस्वी वाणी से न केवल मालवा बल्कि पूरे देश में धर्म जागरण का कार्य किया है।

मालवा में रहना सौभाग्य की बात- मंच से संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि हम सभी का यह बड़ा सौभाग्य है कि हम मालवा में रहते हैं और यहां ऐसे संत का सान्निध्य मिलता है, जिन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि संत कमल किशोर नागर ने सिर्फ अपने शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों से भी समाज को प्रेरित किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर गोशालाओं की स्थापना कर गौ-सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

संत कमल किशोर में आज भी विनम्रता- विजयवर्गीय ने कहा कि यह मालवा वासियों के लिए

गर्व की बात है कि इतने बड़े संत होने के बावजूद संत कमल किशोर नागर में आज भी वही विनम्रता है जो कई साल पहले देखने को मिली थी। उन्होंने अपने पुराने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि करीब 25 साल पहले सांवेर में उन्होंने पहली बार संत कमल किशोर नागर की कथा सुनी थी और उस समय जो सादगी और विनम्रता उनके व्यक्तित्व में थी वही आज भी दिखाई देती है। नहीं तो जरा सी कथा चालू करी और चार लोग आने लग गए तो कॉलर खड़ी हो जाती है । उन्होंने कहा कि विनम्रता तभी आती है जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है और जो व्यक्ति ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है।

सुर्खियों से सरोकार, बेअसर सरकार, भाजपा राज में ग्रामीण विकास हुआ बदहाल: जीतू पटवारी

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास विभाग को पूरी तरह गर्त में पहुँचा दिया है। सरकार केवल सुर्खियाँ बटोरने में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास की योजनाएँ दम तोड़ रही हैं।

श्री पटवारी ने आगे कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बजट के प्रबंधन और नियोजन को लेकर बेहद लापरवाह साबित हो रही है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित और पोषित योजनाओं के लिए जो बजट आवंटित किया जाता है, उसे भी राज्य सरकार पूरा खर्च नहीं कर पा रही है।

श्री पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार की यह विफलता केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं, बल्कि प्रदेश के ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की उदासीनता को भी दर्शाती है। यदि केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से चलने वाली योजनाओं का बजट भी समय पर खर्च नहीं हो पा रहा है, तो यह स्पष्ट है कि सरकार के पास न तो स्पष्ट योजना है और न ही प्रभावी क्रियान्वयन की इच्छाशक्ति।

श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगातार विभागों की वास्तविक स्थिति उजागर की जा रही है। कल कृषि विभाग की बदहाली का खुलासा किया गया था और आज ग्रामीण विकास विभाग की वास्तविक तस्वीर सामने लाई जा रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए 27,745.18 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, लेकिन 7 मार्च 2026 तक मात्र 11,457.66 करोड़ ही खर्च किए गए हैं। अर्थात कुल बजट का केवल 41.30 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण विकास नहीं, बल्कि केवल घोषणाएँ और प्रचार है।

श्री पटवारी ने कहा कि ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में भी बेहद कम राशि खर्च की गई है, जो सरकार की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। सरकार की लापरवाही, आर्थिक कुप्रबंधन और बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण विकास की योजनाएँ धरातल पर आने से पहले ही चकनाचूर हो जाती हैं और आम जनता को उनका लाभ नहीं मिल पाता।

मां की साड़ी का फंदा बनाकर युवक ने की आत्महत्या

सुसाइड नोट में प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप, रेप केस की धमकी देती थी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक युवक ने मां की साड़ी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। मां ने बेटे का शव रेलिंग पर लटका देखा और तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। घटना स्थल पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मुस्लिम प्रेमिका को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है।

मामला अशोका गार्डन क्षेत्र के सेठी नगर में शनिवार सुबह का है। मृतक की पहचान दीपक गुर्जर (24) के रूप में हुई। सुसाइड नोट में उसने प्रेमिका द्वारा धोखा देने, रेप केस में फंसाने और खुदकुशी के लिए उकसाने का जिक्र किया है।पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर हैंडराइटिंग जांच के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

युवक ने लिखा- शादी का वादा था, इनकार कर दिया

युवक ने सुसाइड नोट में लिखा- मैं दीपक गुर्जर, अशोका गार्डन का निवासी, अपने फैसलों के लिए अपनी प्रेमिका को जिम्मेदार मानता हूं। माही मेरे साथ कई सालों से रिलेशन में है। हमने शादी का वादा किया था, लेकिन अब यह मुझे गुमराह कर रही है, दूसरे लड़के के साथ घूमती है और उससे बात करती है। जब मैं कुछ कहता हूं तो धमकाती है कि जेल भेज दूंगी और रेप का केस लगवा दूंगी। उसने दो दिन पहले मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। हमारी शादी का वादा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह कहती है कि तुम मर भी जाओ तो मेरा कुछ नहीं होगा। मैं बच जाऊंगी। मेरी आत्महत्या की वजह वह और उसका एक दोस्त हैं।

दीपक फेब्रिकेशन का काम करता था और मां-पिता का इकलौता बेटा था। उसके बड़े बहन की शादी हो चुकी है। शव की तलाशी में उसकी पेंट की जेब में एक पर्स मिला, जिसमें डायरी के पेज पर सुसाइड नोट लिखा था। युवक और प्रेमिका का लगभग 6-7 साल पुराना रिश्ता था।

पानी की लाइन में मृत केचुआ... कमिश्नर से शिकायत

भोपाल के मॉडल ग्राउंड का मामला, लोग बोले- इंदौर जैसा हादसे की संभावना

भोपाल (नप्र)। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 34 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में पानी को लेकर सरकार से लेकर अफसर तक अलर्ट हुए हैं, लेकिन भोपाल में अब तक हालात नहीं सुधरे हैं। कहीं गंदा पानी आ रहा है तो कहीं टंकी की सफाई नहीं हुई तो कहीं सीवेज से ही पाइप लाइन गुजर रही है। ऐसे में यहां भी इंदौर जैसे हादसे की संभावना है। ताजा मामला शहर के वार्ड नंबर-9 मॉडल ग्राउंड क्षेत्र में सामने आया है। आईआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी के मोहसिन खान ने बताया कि रमजान महीने के दौरान पुराने भोपाल में खराब स्वच्छता, खुले नालों और सीवेज से संबंधित स्वास्थ्य खतरों को लेकर जिम्मेदार अलर्ट नहीं है। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति पाइप लाइनों में रिसाव और छेद से पानी के दूषित होने का गंभीर खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया, पेयजल टंकी से आसपास के कई इलाकों में पेयजल की सप्लाई होती है।

महंगी किताबें और मनमानी फीस

भड़के अभिभावकों ने भोपाल डीईओ दफ्तर घेरा

दी सड़क पर उतरने की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। निजी स्कूलों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर वसूली जा रही मनमानी फीस और महंगी किताबों के खिलाफ शुक्रवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग की चुप्पी के कारण निजी स्कूल संचालक बेखौफ होकर अभिभावकों की जेब काट रहे हैं।

डीईओ पर मिलीभगत का आरोप- अभिभावकों ने डीईओ को सौंपे गए ज्ञापन में कड़े शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश निजी स्कूल फीस नियम 2020 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। नियमों के मुताबिक, स्कूलों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से 90-180 दिन पहले (31 दिसंबर 2025 तक) अपनी फीस, ऑडिटेड अकाउंट और अन्य वित्तीय जानकारियां सरकारी पोर्टल पर अपलोड करनी थीं। लेकिन अधिकांश स्कूलों ने इसे नजरअंदाज किया है, जिससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि माता-पिता भी अंधेरे में हैं।

क्या हैं मुख्य शिकायतें?

अभिभावकों ने मुख्य रूप से पांच मुद्दों पर प्रशासन को घेरा है। जिनमें महंगी किताबें , यूनिफॉर्म का सिंडिकेट, फीस में मनमानी वृद्धि, ट्रांसपोर्ट चार्ज और बस्ते का बोझ शामिल हैं।

देवेंद्र तिवारी, अध्यक्ष (भोपाल इकाई), मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन ने कहा ज्यादातर स्कूलों ने सालों से फीस का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय उन्हें समय सीमा बढ़ाने की छूट दे रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। हमारे पास सबूत हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया।

क्या बोले जिम्मेदार?

जब इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एन.के. अहिरवार से बात की गई, तो उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अभिभावकों की मांगों और उनके ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है।

आगे का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर लिया जाएगा। हालांकि, इस जवाब से संतुष्ट होने के बजाय अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कलेक्टर या जिला फीस समिति ने सख्त निर्देश जारी नहीं किए, तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे।

क्यों बढ़ी तल्खी?

मध्य प्रदेश में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, हर साल सत्र शुरू होने से पहले किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर सिंडिकेट सक्रिय हो जाता है। नियम कहते हैं कि स्कूल को कम से कम 3 साल तक एक ही किताब चलानी चाहिए, लेकिन कमीशन के चक्कर में हर साल पब्लिशर बदल दिए जाते हैं, जिसका सीधा आर्थिक बोझ मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है।

महिला दिवस विशेष

स्मिता कुमारी
लेखक सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र की निदेशक हैं।

नाम में क्या रखा है: नारी के अस्तित्व का संघर्ष

जब एक पुरुष के लिए यह सामान्य नहीं है, तो एक स्त्री के लिए कैसे हो सकता है? यदि 'नाम में कुछ नहीं रखा', तो पुरुषों के नाम देने की आवश्यकता ही क्या है? और यदि कार्ड में स्थान का अभाव है, तो किसी का नाम देने के बजाय केवल 'समस्त परिवार' क्यों नहीं लिखा जाता? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तब होती है, जब शोक संदेश (मृत्यु पत्र) में भी पुत्री का नाम नहीं होता। क्या विछोह की पीड़ा केवल बेटों को होती है? क्या माता–पिता केवल बेटों के ही गुजरते हैं, बेटियों, बहुओं या दामादों के नहीं? क्या यह व्यवहार उन्हें उनके अपने ही परिवार के बीच 'बेगाना' नहीं बना देता?

कुछ समय पहले एक डॉक्टर की शादी का कार्ड आया। उस कार्ड पर परिवार के सदस्यों की सूची में उनके पालतू कुत्ते का भी नाम था। वहीं दूसरी ओर, समाज में ऐसे निमंत्रण पत्र भी बहुतायत में देखे जाते हैं जिनमें घर की बेटी, बहन, भाभी, बुआ या चाची का नाम तक नहीं होता। समाज के अधिकतर घरों की परंपराएँ हर मोड़ पर महिलाओं के अस्तित्व को गौण करने के लिए दृढ़ता से खड़ी हैं। प्रश्न यह है कि क्या कार्ड पर भाई, चाचा या दादा का नाम न हो, तब भी उनके साथ रिश्ते सामान्य माने जाएंगे? क्या वे पुरुष उस उत्सव में शामिल होंगे, जहाँ निमंत्रण पत्र पर उनका नाम न हो?

जब एक पुरुष के लिए यह सामान्य नहीं है, तो एक स्त्री के लिए कैसे हो सकता है? यदि 'नाम में कुछ नहीं रखा', तो पुरुषों के नाम देने की आवश्यकता ही क्या है? और यदि कार्ड में स्थान का अभाव है, तो किसी का नाम देने के बजाय केवल ÷समस्त परिवार÷ क्यों नहीं लिखा जाता? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तब होती है, जब शोक संदेश (मृत्यु पत्र) में भी पुत्री का नाम नहीं होता। क्या विछोह की पीड़ा केवल बेटों को होती है? क्या माता-पिता केवल बेटों के ही गुजरते हैं, बेटियों, बहुओं या दामादों के नहीं? क्या यह व्यवहार उन्हें उनके अपने ही परिवार के बीच 'बेगाना' नहीं बना देता?

एक तरफ समाज में बेटा-बेटी की समानता का ढोल पीटा जाता है, विद्वान तर्क देते हैं, कवि कविताएँ लिखते हैं और सरकार योजनाएँ गिनाती है; वहीं दूसरी ओर, मानसिक हिंसा से जूझती स्त्रियाँ समाज की इन कुरीतियों से लड़ रही हैं या इसे ही अपनी नियति मानकर जी रही हैं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे 'सीखी हुई बेबसी' (Learned Helplessness) कहते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति कई बार दोयम दर्जे से भी नीचे प्रतीत होती है। इन निमंत्रण पत्रों को देखकर यह एहसास होता है कि कई घरों में महिलाओं का स्थान पालतू जानवरों से भी नीचे है, जबकि वे हर उत्सव में बराबर की जिम्मेदारी निभाती हैं।

स्त्रियों के अस्तित्व का दूसरा बड़ा संघर्ष पैतृक संपत्ति के अधिकार को लेकर है। कानून बने लगभग 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार के पास महिलाओं को मिले संपत्ति अधिकार का सटीक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। शायद पुरुष-प्रधान सत्ता में बैठे लोगों को अपनी बहन-बेटियों को अधिकार देने की कोई जल्दी भी नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि बेटियों को 'दहेज' दे दिया गया, इसलिए संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं बनता। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या वह दहेज वास्तव में बेटी को मिलता है? क्या परिवार अपने बेटों की शादियों पर खर्च नहीं करते? और उनका क्या, जिन्हें दहेज भी नहीं मिला?

कहा जाता है कि बेटियों को मायके में सम्मान तभी मिलता है, जब वे संपत्ति में हिस्सा नहीं माँगतीं। क्या वास्तव में खाली हाथ मायके जाने वाली बेटियों को मान मिलता है? वास्तविकता तो यह है कि जो बेटी जितने मान-सम्मान के उपहार साथ लेकर आती है, उसे वैसा ही सत्कार मिलता है। यह व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा भाई-भाई या अन्य रिश्तेदारों के बीच होता है। इसका अर्थ है कि मायके में छोड़ी गई संपत्ति का स्त्रियों के पक्ष में कोई भावनात्मक महत्व नहीं रह जाता। जिस घर को वह अपना मानती थी और जिसे शादी के बाद अपना समझ रही थी, वे दोनों ही उसके नहीं होते। इस आघात को 'ट्रॉमेटिक रियलिटी शॉक' (Traumatic Reality Shock) कहते हैं, जिससे कई मानसिक और भावनात्मक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अक्सर तर्क दिया जाता है कि संपन्न घर में ब्याही बेटी को भाई से हिस्सा क्यों लेना चाहिए? यहाँ दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली–यह हिस्सेदारी भाई की संपत्ति में नहीं, बल्कि पिता की संपत्ति में होती है। पितृसत्तात्मक परवरिश में लड़कियों को 'पराया धन' और लड़कों को 'उत्तराधिकारी' माना जाता है, जिससे इस आर्थिक प्रताड़ना का सामान्यीकरण (Generalization) कर दिया जाता है। दूसरी बात–कितने संपन्न भाइयों ने अपनी बहन के लिए अपना हिस्सा छोड़ा है? एक संपन्न भाई अपने कमजोर भाई के लिए एक इंच जमीन नहीं छोड़ता और उसके लिए कोर्ट-कचहरी तक कर लेता है, जिसे समाज 'हक की लड़ाई' कहता है। किंतु यदि बहन अपने हिस्से की बात करे, तो उसे न जाने कितने अपमानजनक शब्दों से नवाज़ा जाता है।

यदि समाज में स्त्रियों को पूर्ण रूप से पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो, तो उनके साथ होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा में भारी कमी आएगी। एक केस में एक महिला ससुराल में हिंसा इसलिए सह रही है क्योंकि उसका पूरा दिन दिव्यांग बच्चे की देखभाल में निकल जाता है। वह नौकरी नहीं कर सकती और उसके पास रहने के लिए मायके का सहारा भी नहीं है। भाई-बहन का भाई के लिए या बहन के लिए पैतृक संपत्ति का अधिकार छोड़ना किसी की अपनी इच्छा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं।

तीसरा संघर्ष गृहणियों का है। बिना छुट्टी के काम करने वाली इन महिलाओं को पति के घर में भोजन और छत तो मिल जाती है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलता। यदि उन्हें उनके श्रम का पारिश्रमिक मिले, तो वे भी अपनी निर्णय क्षमता सिद्ध कर सकती हैं। जो स्त्रियाँ विमान उड़ा सकती हैं, उनमें उसे खरीदने की परख भी होगी। आज भी बड़े बजट की खरीदारी में महिलाओं की राय लेना पितृसत्तात्मक सोच को खटकता है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा, विवाह की आयु, संतान की संख्या, नौकरी का स्वरूप, पहनावा, मित्रता और यहाँ तक कि हँसने की मर्यादा भी अक्सर पिता, भाई, पति या पुत्र ही निर्धारित करते हैं। सबसे अधिक हिंसा उन्हीं महिलाओं के साथ होती है, जिनके मायके वालों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। जिस घर में स्त्री ने जन्म लिया, जिसे अपना समझकर सहेजा, जब वहीं से उसे मानसिक रूप से तोड़ा जाता है, तो किसी अनजान घर में उसकी मजबूती की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आज अनगिनत महिलाएँ अपने अस्तित्व और नाम के लिए गुमनाम संघर्ष कर रही हैं। उनकी खामोशी भी एक संघर्ष है–अपने ही घर से अपना नाम मिटाए जाने के विरुद्ध एक मूक विद्रोह।

महिला दिवस विशेष

उनकी भूमिका

मोहन वर्मा

अपने जन्म से लेकर अन्तिम साँस तक
वे निभाती रहती हैं जीवन के रंगमंच पर
तरह-तरह की भूमिकाएं ।
हमारे चेहरे पर पल पल आने वाले, रंगों की तरह ही
बदलता रहता है
उनके जीवन का रंगबिरंगा या बदरंगा कैनवास ।

कहीं जनम पर अनचाही-करमजली कहकर
पल पल लड़की होने का एहसास दिलाया जाता रहा उन्हें
तो कहीं लक्ष्मी मानकर दुलार की बरसात भी की गई

होश संभालते और समझ आते आते
वे कब सीख गई भेड़ और भेड़ियों मे फर्क़
वे खुद नहीं जानती
लड़की होने की अपनी नियति से अभिशप्त
गर्दन झुकाये चली जाती हैं वे
अपनों के बीच से परायों के बीच

और भला बुरा सब कुछ स्वीकार लेती हैं
भाग्य का लिखा मानकर
खपा देती हैं अपनी सारी उम्र- एक नये संसार में ।

बचपन में कई बार माँ-पिता के अबोले में
अपनी मासूमियत और उम्र से ज्यादा समझदारी से
सुलह कराती या फिर भाई का बचाव करती वे
अपनी उसी समझदारी से करते रहती मध्यस्थता
पिता और पुत्र के बीच भी-उनकी अनबन में
बनकर उनका निवाला-जब वे कहते ÷भूख नहीं है÷।

घर के रिश्तों और भावनाओं को
एक मजबूत डोर से बाँधकर रखती हैं वे
बहू से सास बन जाने के बाद भी /बरसों बरस घर
उनके मजबूत कंधों के भरोसे निश्चिंत रहता है
और निश्चिंत रहते है वे सब भी-
जिनके भरोसे घर - घर माना जाता है ।

और एक दिन यकायक
नाटक के निर्देशक के इशारों पर
जीवन के रंगमंच पर खत्म हो जाती है उनकी भूमिका
कि अचानक एहसास होता है उनके न होने का
एक अंतहीन उदासी पसर जाती है
जब बोलती दीवारें बोलना बन्द कर देती है
खिले फूल दिखाई देने लगते हैं बेज़ान से
रंग हो जाते हैं बेरंग
क्योंकि लौट जाती हैं वे अपने सारे रंग समेटकर
जीवन के रंगमंच पर ख़त्म हो जाती है उनकी भूमिका ।।

औरतें, घर से बाहर

रामेश्वरम तिवारी

औरतें पढ़-लिखकर
अवनि को नापने लगी हैं
अंबुधि को मथने लगी हैं
परिंदों-सी अपने पर फैलाकर
सरहदों को लाँघकर
अंबर में उड़ान भरने लगी हैं।

जो मृगी कल तक
भयाक्रांत थी आखेटकों से
आज खुद आखेटकों का
आखेट करने में लगी हुई हैं।

गर्व से सिर ऊँचाकर
घूँघट के पट खोलकर
सबको दिखा देना चाहती है
वह किसी भी नज़रिए से
आदमी के पीछे नहीं
वरन् कँधा मिलाकर खड़ी हैं।

उसने आज़ादी का
अमृत आस्वादन कर लिया है
सालों-सदियों की
दासता की ज़ंजीरें तोड़कर
घर से बाहर निकल आयी हैं।

महिला दिवस

महिलाओं की सुरक्षित सहभागिता का समय

संध्या अग्रवाल
लेखक साहित्यकार हैं।

हर वर्ष महिला दिवस पर सम्मान और सशक्तिकरण की बातें ज़ोर-शोर से होती हैं। पर क्या सचमुच महिलाओं का दैनिक जीवन उतना ही सुरक्षित और सम्मानजनक है, जितना मंचों से बताया जाता है? यही वह प्रश्न है, जो उत्सव के बीच भी हमें ठहरकर सोचने को मजबूर करता है।

हर वर्ष महिला दिवस आते ही सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण की चर्चाएँ तेज़ हो जाती हैं। मंच सजते हैं, भाषण होते हैं और उपलब्धियों के उदाहरण गिनाए जाते हैं। लेकिन असली प्रश्न आज भी वही है – क्या महिलाओं का रोज़मर्रा का जीवन उतना ही सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और अवसरपूर्ण बन पाया है, जितना इन मंचों पर दिखाई देता है? आधी आबादी की वास्तविक और सुरक्षित सहभागिता के बिना किसी भी समाज का संतुलित विकास संभव नहीं।

निस्संदेह पिछले वर्षों में शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। छोटे शहरों और कस्बों की बेटियाँ अब सीमाएँ तोड़कर अपनी पहचान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी योजनाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नए रास्ते खोले हैं। यह परिवर्तन समाज में सकारात्मक चेतना का संकेत है।

फिर भी चुनौती केवल अवसर उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि सामाजिक सोच बदलने की है। आज भी अनेक परिवारों में लड़की की शिक्षा को निवेश नहीं बल्कि खर्च माना जाता है। कार्यस्थलों पर सुरक्षा, समान अवसर और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी जैसे प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में तो कई प्रतिभाएँ सामाजिक दबाव और असुरक्षा की भावना के कारण आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाती हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल नौकरी या आय नहीं, बल्कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण वातावरण है। जब घर में बेटी की राय सुनी जाएगी, स्कूल में उसे बराबरी का मंच मिलेगा और समाज उसकी उपलब्धियों को सहज रूप से स्वीकार करेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन दिखाई देगा।

इस दिशा में शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है। केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी उतने ही आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि रहे, और उसी के साथ उन्हें अवसर तथा विश्वास भी मिले। सुरक्षित वातावरण ही उन्हें आगे बढ़ने का वास्तविक आत्मबल देता है।

महिला दिवस को केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय इसे सामाजिक आत्ममंथन का अवसर बनाया जाना चाहिए। यदि परिवार, संस्थाएँ और समाज मिलकर सुरक्षा, समान अवसर और सम्मान की संस्कृति विकसित करें, तो सशक्तिकरण किसी विशेष दिन का विषय नहीं रहेगा, बल्कि सामान्य जीवन व्यवहार बन जाएगा। महिलाओं की प्रगति केवल उनका अधिकार नहीं, समाज की आवश्यकता है। जब सुरक्षा, अवसर और विश्वास साथ चलेंगे, तभी सशक्तिकरण सचमुच जीवन में उतरेगा।

व्यंग्य

भाषा की मर्दानगी और महिला सशक्तिकरण का व्याकरण

सुदर्शन कुमार सोनी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

संजब तक शब्दों की गद्दी पर पुरुष बैठे रहेंगे, बराबरी की कुर्सी हमेशा फोल्डिंग ही रहेगी। हर साल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश में महिला सशक्तिकरण की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। मंच सजते हैं, भाषण होते हैं, और समाज गर्व से घोषणा करता है कि अब महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच एक छोटी-सी समस्या चुपचाप मुस्कुरा रही होती है–हमारी भाषा। क्योंकि भाषा का लोकतंत्र भी अजीब है–वोट सबके बराबर हैं, लेकिन शब्दों की कुर्सी पुरुषों के लिए आरक्षित है।

दरअसल असली खेल संसद विधानसभाओं या समाज में नहीं, शब्दकोष में खेला गया है। शब्द इतने चतुराई से बनाए गए हैं कि पुरूषोचित चौधराहट ही हमेशा छायी रहे । उदाहरण के लिए 'पुरुषार्थ' शब्द को ही देख लीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष–ये जीवन के चार लक्ष्य बताए गए। लेकिन इनका नाम पड़ा पुरुषार्थ। अब अगर कोई स्त्री वही सब हासिल कर ले तो क्या कहेंगे? 'स्त्रीयार्थ'? यह शब्द तो किसी को याद नहीं आता। पुरुषार्थ का मतलब ही बता देता है कि सफलता का पेटेंट किसके नाम लिखा गया है।स्त्री अपने दम पर आईएएस भी बन जाए तो कहेंगे कि उसने पुरूषार्थ का परिचय दिया। रामचरितमानस को सीताचरितमानस क्यों नही कहा गया।करवा चौथ का विधान कर पतिव्रता शब्द गढ़ दिया , पत्नीव्रती क्यों भेजे मे नही आया।भाषा का संविधान भी बड़ा दिलचस्प है। ऊपर से बराबरी लिखी है, लेकिन नीचे फुटनोट में लिखा रहता है–'शर्तें लागू'। यानि पुरुषों का वीटो लगा हुआ है।

अब 'मसीहा' शब्द को ही देख लीजिए। संकट आए तो लोग कहते हैं–कोई मसीहा आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन यह मसीहा अपने आप पुरुष ही क्यों होता है? ÷मसीही÷ शब्द किसी को याद नहीं आता। लगता है जैसे भाषा ने तय कर लिया हो कि उद्धार का ठेका पुरुषों के पास ही रहेगा। भाषा की यह चालाकी ताकत के शब्दों में और साफ दिखती है। 'पहलवान' शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में मूंछों वाला एक भारी-भरकम आदमी उभर आता है। लेकिन अगर वही ताकत किसी महिला में दिख जाए तो तुरंत उसके आगे 'महिला' जोड़ना पड़ता है–पहलवान अगर पुरुष है तो बस पहलवान, और अगर स्त्री है तो पहले 'महिला' जोड़कर अनुमति लेनी पड़ेगी।

पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है कन्या रत्न की कभी नही। पुत्री अच्छा कार्य करे तो मेरा बेटा हो जाती है पुत्र अच्छा कार्य करे तो मेरी बेटी कंहा गयी। और सबसे दिलचस्प मामला है 'वेश्या' शब्द का। अगर वही काम पुरुष करे तो भाषा अचानक शर्मीली हो जाती है। उसके लिए कोई लोकप्रिय शब्द नहीं मिलता।

असल में भाषा सीधे-सीधे भेदभाव नहीं करती, बस धीरे-धीरे समझा देती है कि किसकी गलती गलती नहीं है और किसकी मजबूरी भी अपराध है। इसलिए भाषा इतनी समझदार है कि पुरुष की गलती भी 'शरारत' बन जाती है और स्त्री की मजबूरी 'चरित्र' बन जाती है।

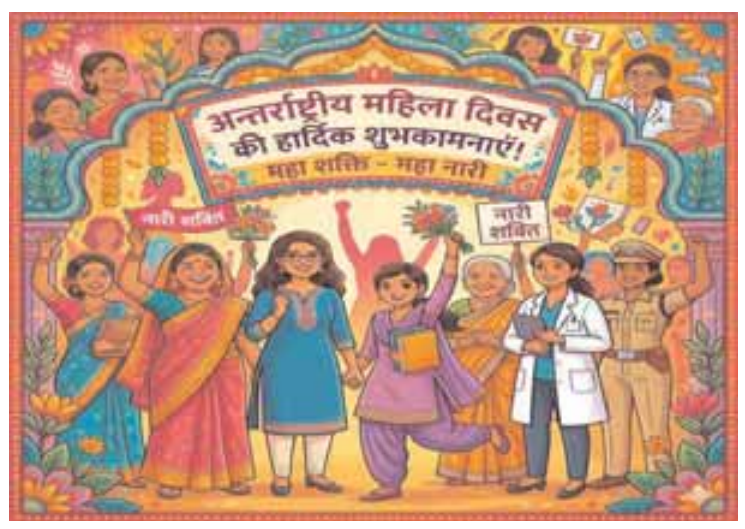

सत्तासुंदरी के शब्दों में भी यही कहानी दिखाई देती है। किसी महिला को देश का सर्वोच्च पद मिल जाए तो वह राष्ट्रपति ही कहलाती है। लेकिन जैसे ही नीचे की कुर्सियों की बात आती है, लोग ÷मंत्राणी÷, 'नेत्री', 'अध्यक्षा' जैसे प्रयोग करने लगते हैं। मानो भाषा कह रही हो–ऊपर तक तो ठीक है, लेकिन नीचे आते-आते पहचान अलग करनी पड़ेगी।

इसी तरह 'अधिकारी' शब्द है। महिला भी अधिकारी ही कहलाती है, लेकिन 'अधिकारिणी' शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी संस्कृत नाटक की पंक्ति सुन ली हो। भाषा का यह खेल इतना महीन है कि हमें पता भी नहीं चलता और बराबरी धीरे-धीरे फाइलों में अटक जाती है। शब्दकोष में बराबरी ढूँढना वैसा ही है जैसे त्वरित न्याय। है।गंगाधर को एक और पीड़ा है कि स्त्री इसके लिए बिल्कुल भी सजग नही है। वह तो महिला दिवस के आयोजन से ही अभिभूत है। सुंदरकांड का आयोजन कर पुरूषों के साथ उत्साह पूर्वक ढोर गंवार शूद्र व नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी पंक्ति भी गाती है ।

इस पूरे मामले की असली विडंबना यह है कि समाज ने महिलाओं को मंच तो दे दिया, माइक्रोफोन भी थमा दिया, लेकिन शब्दों की चाबी अब भी पुरुषों के पास है। समाज ने महिलाओं को पंख तो दिए, लेकिन उड़ान का शब्दकोष अब भी पुरुषों के पास है।

यही वजह है कि महिला सशक्तिकरण की असली लड़ाई संसद, अदालत या सड़क पर नहीं, बल्कि भाषा के अंदर चलनी चाहिए। भाषा के अनेक शब्द तो स्त्री को कदम-कदम पर छलनी करते हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा पुरुष नहीं, बल्कि पुरुषों द्वारा बनाया गया शब्दकोष है।

और जब तक शब्दों की गद्दी पर वही पुराने मालिक बैठे रहेंगे, तब तक बराबरी की कुर्सी स्थायी नहीं होगी। हमेशा फोल्डिंग ही रहेगी। स्त्रियों हर जगह आप शब्दों की बेड़ियों में हो आपको कुछ और नही केवल इसे तोड़ना है बाकी कार्य अपने आप हो जाएगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

महिलाओं की बढ़ती उड़ान और सामने खड़ी चुनौतियाँ

डिजिटल दुनिया
ममता कुशवाहा
लेखक शिक्षक हैं।

डिजिटल युग ने मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। संचार, शिक्षा, व्यापार, शासन और सामाजिक संबंधों के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया है। इंटरनेट के तीव्र प्रसार, नई तकनीकों के विकासऔर डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार ने दुनिया भर के लोगों के लिएअभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। इस बदलते दौर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि महिलाओं की डिजिटल क्षेत्र में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज महिलाएँ केवल तकनीक का उपयोग करने वाली उपभोक्ता भर नहीं रह गई हैं,बल्कि वे नवाचार करने वाली, उद्यमी, शिक्षिका और नेतृत्वकारी भूमिकानिभाने वाली सक्रिय शक्ति बनती जा रही हैं। वे डिजिटल दुनिया के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर भी इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद महिलाओं को कई सामाजिक, संरचनात्मक और तकनीकीचुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो डिजिटल क्षेत्र में उनकी पूर्णभागीदारी को सीमित करती हैं।

डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी का सबसे स्पष्ट रूप शिक्षा और जानकारी तक उनकी बढ़ती पहुँच में दिखाई देता है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय, वेबिनार और वर्चुअल कक्षाएँ महिलाओं और लड़कियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के नए द्वार खोल रही हैं। पहले अनेक महिलाएँ पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक प्रतिबंधों या आर्थिक सीमाओंके कारण विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुँच पाती थीं। लेकिन आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से वे घर बैठे ही नई-नई जानकारियाँप्राप्त कर सकती हैं और अपने कौशल का विकास कर सकती हैं। इससे न केवलउनके ज्ञान का विस्तार हुआ है बल्कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरताभी बढ़ी है। डिजिटल शिक्षा ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एकमहत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भी महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों के नए रास्तेखोले हैं। ई- कॉमर्स वेबसाइटें, ऑनलाइन बाजार और डिजिटल भुगतानप्रणालियाँ महिलाओं को कम निवेश में अपना व्यवसाय शुरू करने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। आज अनेक महिलाएँ घर से ही अपने बनाए हुए उत्पाद, जैसेहस्तशिल्प, कपड़े, घरेलू वस्तुएँ या अन्य सेवाएँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के साधनों की सहायता से वे अपने ग्राहकों तक दूर-दूर तक पहुँच बना पा रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिल रहा है और वे परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस प्रकार डिजिटल माध्यमों के कारणमहिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है और धीरे-धीरे समाज में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं में भी बदलाव दिखाई देने लगा है।

तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी महिलाओं की उपस्थिति धीरे-धीरे मजबूतहोती जा रही है। आज महिलाएँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा विश्लेषक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटर और तकनीकी शोधकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। कई महिलाएँ बड़ी तकनीकी कंपनियों, स्टार्टअप्स और डिजिटलपरियोजनाओं का नेतृत्व भी कर रही हैं। उनके विचार और दृष्टिकोण तकनीकी विकास को अधिक विविध और रचनात्मक बना रहे हैं। विश्व भर की सरकारें औरअंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्नयोजनाएँ और कार्यक्रम चला रही हैं, ताकि तकनीकी क्षेत्रों में मौजूदलैंगिक असमानता को कम किया जा सके।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी महिलाओं को अपनी बात रखने और समाज सेजुड़ने का एक सशक्त माध्यम प्रदान किया है। आज महिलाएँ डिजिटल मंचों केमाध्यम से सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाती हैं, अपने अनुभव साझा करतीहैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी देती हैं और लैंगिक समानता की वकालत करती हैं। महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल पर समान अवसर और सामाजिक न्याय से जुड़े कई आंदोलन डिजिटल माध्यमों के कारण वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी आवाज़ को व्यापक समाज तक पहुँचाने का अवसर दिया है, जिससे सार्वजनिक विमर्श परउनका प्रभाव बढ़ा है।

हालाँकि इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद डिजिटल युग में महिलाओं कीभागीदारी अभी भी समान और संतुलित नहीं है। इसके सामने कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या डिजिटल लैंगिक अंतर (डिजिटल जेंडर डिवाइड) की है। दुनिया के कई हिस्सों, विशेषकर विकासशील देशों में, महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएँ कमउपलब्ध हैं। आर्थिक असमानता, सामाजिक मान्यताएँ और पारिवारिक प्रतिबंध कईबार महिलाओं को डिजिटल तकनीक के उपयोग से दूर रखते हैं। कुछ रूढ़िवादी समाजों में परिवार महिलाओं के इंटरनेट उपयोग को लेकर संदेह या डर कीभावना रखते हैं, जिससे उनकी डिजिटल दुनिया तक पहुँच सीमित हो जाती है। इसप्रकार तकनीक तक समान पहुँच न होने के कारण महिलाएँ डिजिटल अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर उत्पीड़न की समस्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को अक्सर अपमानजनक टिप्पणियों, ट्रोलिंग, धमकियों और पीछा करने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से महिला पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी महिलाएँ कई बार संगठित ऑनलाइन हमलों का लक्ष्य बन जाती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ कई महिलाओं को अपनी राय खुलकर व्यक्त करने से रोक देती हैं। लगातार होने वाला साइबर उत्पीड़न मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है, जिससे कई महिलाएँ डिजिटल मंचों से दूरी बना लेती हैं।

तकनीकी नेतृत्व में महिलाओं की कम उपस्थिति भी एक गंभीर चिंता का विषय है। हालाँकि तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, फिर भी उच्च नेतृत्व पदों पर उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। कई बार लैंगिकभेदभाव, असमान अवसर और कार्यस्थल पर पक्षपात जैसी स्थितियाँ महिलाओं के करियर विकास में बाधा बनती हैं। वेतन असमानता, मार्गदर्शन की कमी और सहयोगी कार्य वातावरण का अभाव भी महिलाओं के सामने चुनौतियाँ खड़ी करता है। इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर किए बिना तकनीकी क्षेत्र में वास्तविक लैंगिक समानता स्थापित करना कठिन है।

डिजिटल साक्षरता की कमी भी महिलाओं की प्रगति में एक महत्वपूर्ण बाधा है। तकनीक तक पहुँच होना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उसका सही और प्रभावी उपयोग करना आना। ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों की कई महिलाएँ डिजिटल उपकरणों, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित नहीं होतीं। इसके कारण वे डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने और उससे लाभ प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसलिए सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएँ भी कई बार महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को प्रभावित करती हैं। अनेक समाजों में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें और पेशेवर या तकनीकी क्षेत्रों में कम समय दें। ऐसी सामाजिक धारणाएँ महिलाओं को नए अवसरों की खोज से रोकती हैं। इसके अलावा यह रूढ़िवादी धारणा भी प्रचलित है कि तकनीक का क्षेत्र केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त है। यह सोच कई लड़कियों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने से हतोत्साहित करती है। इन रूढ़ियों को बदलने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक सामाजिक वातावरण की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सरकारों को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो सस्ती इंटरनेट सेवाएँ, मजबूत डिजिटल ढाँचा और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें। तकनीकी कंपनियों को ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हों और साइबरउत्पीड़न को रोकने के प्रभावी उपाय प्रदान करें। शैक्षणिक संस्थानों कोलड़कियों को विज्ञान और तकनीक के विषयों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें मार्गदर्शन तथा अवसर प्रदान करने चाहिए।

सामुदायिक स्तर पर चलाए जाने वाले कार्यक्रम भी महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डिजिटल कौशल, ऑनलाइन व्यवसाय और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ते हैं। जब महिलाएँ डिजिटल रूप से सशक्त होती हैं तो वे केवल अपने जीवन में ही परिवर्तन नहीं लातीं, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के व्यापक विकास को गति देता है, जिससे बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, स्वास्थ्य सेवाएँ सुधरती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।

डिजिटल युग महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, नवाचार और नेतृत्व के अनेक अवसर लेकर आया है। शिक्षा, उद्यमिता, तकनीक और सामाजिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। फिर भी डिजिटल समानता की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। डिजिटल अंतर, साइबर उत्पीड़न, नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व और डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से ही संभव है। यदि महिलाओं को डिजिटल दुनिया में समान अवसर, संसाधन और सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वे एक अधिक समावेशी, रचनात्मक और न्यायपूर्ण भविष्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

'गिव टू गेन' की थीम और महिला दिवस के मायने

महिला दिवस पर विशेष
चित्रा माली
सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि केंद्र, कोलकाता।

भारत में नारीवादी संगठनों के द्वारा 8 मार्च 1980 को महिलाओं के साथ होने वाले सबसे घृणित अपराध/हिंसा बलात्कार के विरुद्ध मार्च निकाला गया था। जिसमें नारीवादी संगठनों के सदस्यों के साथ यूनिवर्सिटी,कॉलेज के छात्र और छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इसके पूर्व 1978 में हैदराबाद में 'रमिज़ा बी' के साथ हुए बलात्कार और उसके पति की निर्मम हत्या की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया था लेकिन सत्र न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया था। सत्र न्यायालय के इस निर्णय का विरोध महिला संगठनों के द्वारा किया गया था। 1979 में महिला संगठनों ने बलात्कार के विरोध में गुवाहाटी में रैलियां आयोजित की थीं। सामूहिक बलात्कार के विरोध में संथाल परगना (झारखंड) में भी अभियान चलाया गया था। भारत में बलात्कार के मुद्दे को 70 के दशक के अंत में सार्वजनिक एजेंडे में तब रखा गया था जब महिला समूहों और संगठनों ने महाराष्ट्र में एक आदिवासी लड़की मथुरा के पुलिस बलात्कारियों को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आवाज उठाई थी। जिसे हम 'मथुरा कांड' या 'मथुरा बलात्कार कांड' के नाम से जानते हैं। न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ चार वरिष्ठ वकीलों ने एक खुला पत्र लिखा था जिससे प्रेरित होकर बंबई के नारीवादी संगठन फोरम अगेंस्ट रेप (जो अब खुद को फोरम अगेंस्ट आप्रेसन ऑफ वीमेन कहता है) मंच ने इस मामले को दुबारा खुलवाने का निर्णय लेते हुए देश के समस्त महिला संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पत्र लिखा। पत्र पर अमल करते हुए देशभर के नारीवादी संगठन पहली बार किसी राष्ट्व्यापी अभियान में एक साथ शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महिला हिंसा और बलात्कार का विरोध 70 के दशक से ही शुरू हुआ। वैश्विक स्तर पर पहला 'रिक्लेम द नाइट आंदोलन' 12 नवंबर 1977 को लीड्स में हुआ था जिसके अंतर्गत विरोध प्रदर्शन मार्च का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन लीड्स क्रांतिकारी नारीवादी समूह के द्वारा किया गया था। जिसकी प्रेरणा जर्मनी में 30 अप्रैल 1977 को बलात्कार और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विरोध में कई शहरों में निकाले गए मार्च से ली गई थी। इसके पूर्व 70 के दशक में ही अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 1975 में जब सुसान 'सू' अलेक्जेंडर स्पीथ की हत्या काम से घर लौटते समय कर दी गई थी तब इस घटना के विरोध में नारीवादी समूह 'वीमेन अगेंस्ट वायलेंस एंड पोर्नोग्राफी इन मीडिया' ने भी एक सम्मेलन का आयोजन किया था और बाद में विरोध मार्च निकाला था। 'रिक्लेम द नाइट आंदोलन' 'यॉर्कशायर रिपर' हत्याकांड और पुलिस द्वारा महिलाओं को दिए गए निर्देश के खिलाफ था जिसमें महिलाओं को रात के बाद सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने के लिए की नसीहत दी गई थी। लीड्स में मार्च दो स्थानों से शुरू हुआ पहला चैपलटाउन से जिसमें 30 महिलाओं ने हिस्सा लिया और दूसरा वुडहाउस से जिसमें 85 महिलाओं ने सहभागिता की थी। इसके अतिरिक्त लीड्स क्रांतिकारी समूह की महिलाओं के प्रयासों से इसी रात इन शहरों में यॉर्क, ब्रिस्टल, ब्राइटन, न्यूकैसल, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लैंकेस्टर और लंदन में भी विरोध मार्च हुए थे। इसी प्रकार की नसीहतें भारत में भी महिलाओं को दी जातीं रही हैं और साथ ही कपड़ों से लेकर रहन सहन के तरीकों पर भी विशेष ज्ञान दिया जाता रहा है लेकिन हमारे यहां इन नसीहतों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन या मार्च का आयोजन नहीं किया जाता है क्योंकि इन सब तरह की नसीहतों को सोशल कंडीशनिंग के चलते हम सुरक्षा और संरक्षण के लिहाज से स्वीकार करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में कोई कमी नहीं आयी है। सोहो में 1978 में हुए एक मार्च के दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी जिसमें कई महिलाएं घायल हुई और पुलिस ने 13 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद सोहो में ही एक वर्ष बाद आयोजित मार्च में 2,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा,बलात्कार और सार्वजनिक स्थानों पर निर्बाध रूप से आवागमन के लिए, महिलाओं के एक साथ आने के महत्व पर जोर दिया गया था।

1987 बेलफ़ास्ट में 'रिक्लेम द नाइट' मार्च विरोध प्रदर्शन हुआ था। यह मार्च सिटी हॉल तक किया गया था और इसमें बेलफ़ास्ट रेप सेंटर व स्ट्रैनमिलिस कॉलेज सहित विभिन्न संगठनों की महिलाएं शामिल थीं। 1990 के दशक में 'रिक्लेम द नाइट' आंदोलन के अंतर्गत होने वाले विरोध प्रदर्शन बंद हो गए थे। वर्ष 2004 में नारीवादी संगठनों ने 'रिक्लेम द नाइट आंदोलन' और प्रदर्शन को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। इस वर्ष,लंदन में आयोजित प्रदर्शन में केवल 30 महिलाएं ही शामिल हुईं, लेकिन अगले वर्ष 2005 में लगभग 1,000 महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। 2006 में पांच यौनकर्मियों की हत्याओं के जवाब में इप्सविच में 'रिक्लेम द नाइट' विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। जिसमें 200 से 300 लोग शामिल हुए थे। बर्मिंघम में पहला 'रिक्लेम द नाइट' मार्च अक्टूबर 2009 में हुआ था। वर्ष 2010 लंदन में 2500 महिलाओं ने शहर में मार्च किया था और लीड्स में 200 से अधिक महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन मार्च किया था। वर्ष 2013 में नॉर्थम्पटन में पहला 'रिक्लेम द नाइट' मार्च हुआ था, जिसमें पुरुषों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी। मार्च का उद्देश्य नॉर्थम्पटनशायर रेप एंड इनसेस सेंटर (एनआरआईसीसी) के लिए जागरूकता को बढ़ाना भी था। वर्ष 2017 में #MeToo आंदोलन से प्रेरित सैकड़ों महिलाओं ने लंदन,ब्रिस्टल,न्यूकैसल और यूनाइटेड किंगडम में मार्च किए थे। वर्ष 2021 में सारा एवरार्ड की मृत्यु के विरोध में लीड्स में एक कैंडल मार्च आयोजित करने की कोशिश की गई थी,लेकिन इसे पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। जिससे विरोध प्रदर्शन आभासी माध्यम से (ऑनलाइन) हुआ और इसमें 28,000 से अधिक लोगों ने शिरकत की,जिसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर स्ट्रीम किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 'रिक्लेम द नाइट' मार्च 1978 में आयोजित किए गए,जो पहले पर्थ और सिडनी में हुए थे और फिर 1979 में मेलबर्न में हुए थे। वर्ष 2017 लजुब्लजियाना में 'रिक्लेम द नाइट' विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। वर्ष 1978 में, अमेरिका में पहली बार 'रिक्लेम द नाइट' मार्च का आयोजन किया गया था। जिसमें 50 राज्यों की 5,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। भारत में वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद 'रिक्लेम द नाइट' रात को पुनः प्राप्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन मार्च हुए थे। विरोध प्रदर्शन के लिए नव-वर्ष की पूर्व संध्या को चुना गया था। इस दिन 20 अलग-अलग शहरों में सैकड़ों महिलाओं ने सामूहिक बलात्कार के विरोध में मार्च प्रदर्शन और कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके बाद भारत में ही वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में हजारों महिलाओं और पुरुषों ने 'रिक्लेम द नाइट' मार्च 'मेयरा रात डोखोल कोरो' (रिक्लेम द नाइट का बांग्ला अनुवाद) रात को पुनः प्राप्त करने के लिए मार्च और कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिस प्रकार से निर्भया कांड के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए नव-वर्ष की पूर्व संध्या को चुना गया था उसी प्रकार से आर.जी.कर कोलकाता की घटना के विरोध प्रदर्शन के लिए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व रात्रि यानी 14 अगस्त 2024 को 11.55 पर मार्च का समय निर्धारित किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन मार्च के लिए भी सोशल मीडिया पर अपील जारी की गई थी और बहुत ही कम समय में अलग-अलग स्थानों पर एकत्रित होकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन मार्च निकाले थे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला हिंसा और बलात्कार के विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध के संघर्ष को शामिल करने का उद्देश्य महज इतना है कि महिला हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों, अधिनियमों को बनवाने के लिए और रात को पुनः प्राप्त करने के लिए (रिक्लेम द नाईट) नारीवादी संगठनों ने और महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया है और कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन समाज व्यवस्था में दिखाई नहीं देता है। आज भी पीड़िता के लिए न्याय की प्रक्रिया बहुत जटिल है और दुरूह है तथा न्याय प्राप्ति में भी लंबा समय लगता है इसलिए बहुत कम महिलाएं ही अपने साथ होने वाले अपराध की प्राथमिकी दर्ज करती हैं और न्याय के लिए संघर्ष करती हैं। कमाल की बात तो यह भी है कि हमारे देश में न्याय मिलने के बाद भी पीड़िता को न्याय को बरकरार रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बिलकिस बानो और उन्नाव रेप केस की पीड़िता को लिया जा सकता है जिन्होंने न्याय को बरकरार रखने के लिए दुबारा संघर्ष किया है। निर्भया कांड पर दिल्ली क्राइम वेब सीरीज सीजन एक,उन्नाव रेप केस पर सिया और ऐसी कई फिल्में और वेब सीरीज महिला हिंसा और बलात्कार पर बनाई गई है। 20 फरवरी को फिल्म 'अस्सी' रिलीज हुई है जो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध करती दिखाई देती है। इस साल के प्रारंभ में ही मणिपुर में सामूहिक दुष्कर्म (वर्ष 2023 मई) की शिकार हुई एक 20 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया था। पीड़िता की बहन ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि 'कोई उसे न्याय नहीं दिला सका'। यह वाक्य पूरी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिंह लगाता है और साथ ही यह सोचने पर विवश भी करता है कि क्या भारत में पीड़िता को समय पर न्याय मिलता है?

इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रात को पुनः प्राप्त करने के अधिकार के लिए संघर्ष किया जाए जो आजादी के इतने वर्षों बाद भी आधी आबादी को नसीब नहीं हो पाई है आज भी वे अपने समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम 'गिव टू गेन' है जिसका मतलब जब हम देते हैं, तो हमें मिलता है। आधी आबादी ने पुरुषों को बिना किसी संघर्ष के सभी अधिकार प्रदान किए हैं, तो अब पुरुषों से भी यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वे भी आधी आबादी को अपने अधिकारों का उपभोग करने देंगे। यह एक वर्ष भर चलने वाला अभियान है जो लैंगिक समानता को हासिल करने में बढ़ावा देने की मानसिकता को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

महिलाओं ने खुद बदली है अपनी दुनिया

महिला दिवस विशेष
डॉ. मनीष जैसल
लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

भारतीय समाज की संरचना लंबे समय तक ऐसी रही जिसमें महिलाओं की भूमिका को मुख्यतः घर और परिवार तक सीमित मान लिया गया था। सदियों तक सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं ने यह धारणा बनाए रखी कि सार्वजनिक जीवन, निर्णय-निर्माण और नेतृत्व के क्षेत्र पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन इतिहास की गति स्थिर नहीं रहती। समय के साथ-साथ महिलाओं ने केवल इन सीमाओं को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उन्हें तोड़कर अपनी दुनिया को नए अर्थ दिए। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक आंदोलनों और व्यक्तिगत साहस के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। आज राजनीति, विज्ञान, खेल, कला, सिनेमा, संगीत और स्वास्थ्य जैसे लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दिखाई देती है। यह केवल प्रतिनिधित्व का विस्तार नहीं, बल्कि यह उस सोच का परिवर्तन भी है जिसमें महिला को केवल सहायक भूमिका में देखा जाता था। आधुनिक भारत की अनेक महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने काम और संघर्ष से यह साबित किया है कि प्रतिभा और नेतृत्व किसी एक लिंग की बपौती नहीं है।

अगर हम राजनीति की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। 1952 की पहली लोकसभा में कुल 489 सांसदों में केवल 22 महिलाएँ थीं, यानी लगभग 4.5 प्रतिशत। लंबे समय तक यह संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती रही। लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति बदलती दिखाई देती है। 2019 की लोकसभा में 78 महिलाएँ चुनी गईं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है और कुल सदस्यों का लगभग 14 प्रतिशत है। इस बदलाव के पीछे अलग-अलग राज्यों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। पश्चिम बंगाल इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जहाँ से संसद में लगातार बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि पहुँचती रही हैं। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जैसी नेता ने न केवल एक सशक्त क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि जमीनी संघर्ष से राजनीति की दिशा बदली जा सकती है। संसद में भी पश्चिम बंगाल से महुआ मोइत्रा और नुसरत जहाँ जैसी महिला सांसदों ने अपने सक्रिय हस्तक्षेप से राष्ट्रीय बहसों को प्रभावित किया है। बिहार से मीसा भारती और ओडिशा से अपराजिता सारंगी जैसी सांसदों ने भी अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों के साथ संसद में योगदान दिया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया और उस दौर में महिलाओं की राजनीतिक क्षमता को लेकर बने कई पूर्वाग्रहों को तोड़ा। पंचायत स्तर पर स्थिति और भी दिलचस्प है। 1990 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ, जिसके बाद देशभर में लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएँ स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कई जगहों पर महिलाओं ने सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शिक्षा, जल-संसाधन और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संगीत और कला के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी दुनिया को नए ढंग से गढ़ा है। एक समय था जब सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं का गाना या प्रदर्शन करना सामाजिक दृष्टि से सहज नहीं माना जाता था। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरुआत में कई प्रतिभाशाली कलाकारों को केवल इसलिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे महिलाएँ थीं। लेकिन इसी दौर में कुछ महिलाओं ने साहस के साथ परंपराओं को चुनौती दी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से न केवल कर्नाटक संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई बल्कि यह भी साबित किया कि एक महिला कलाकार की पहचान उसकी कला से बनती है, न कि सामाजिक सीमाओं से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किशोरी अमोनकर और गिरिजा देवी जैसी गायिकाओं ने संगीत की परंपरा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। फिल्म संगीत में लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। आज की पीढ़ी में श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान जैसी गायिकाएँ संगीत की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद यह दायरा और बढ़ा है। अब कई युवा महिला कलाकार स्वतंत्र रूप से अपना संगीत तैयार कर रही हैं और सीधे श्रोताओं तक पहुँचा रही हैं। यह परिवर्तन तकनीक और प्रतिभा के मेल से पैदा हुआ है, जिसने कला की दुनिया में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं।

सिनेमा और थियेटर की दुनिया में भी महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक व्यापक हुई है। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अधिकतर फिल्में पुरुष केंद्रित कहानियों पर आधारित होती थीं और पर्दे के पीछे काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। लेकिन समय के साथ यह स्थिति बदली है। अभिनेत्री से निर्देशक बनी अपर्णा सेन ने समानांतर सिनेमा में महिलाओं की संवेदनशील कहानियों को सामने लाने का काम किया। मीरा नायर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को नई पहचान दिलाई। हाल के वर्षों में ज़ोया अख्तर और मेघना गुलज़ार जैसी निर्देशकों ने मुख्यधारा के सिनेमा में मजबूत कहानियों के माध्यम से महिलाओं के अनुभवों को नए ढंग से प्रस्तुत किया है। अभिनय के क्षेत्र में भी स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी जैसी अभिनेत्रियों ने समानांतर सिनेमा में महिला पात्रों को गहराई दी। आज की पीढ़ी में विद्या बालन और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियाँ ऐसे किरदार निभा रही हैं जो पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देते हैं। थिएटर के क्षेत्र में भी उषा गांगुली और नीलम मानसिंह चौधरी जैसी रंगकर्मियों ने मंच को सामाजिक संवाद का माध्यम बनाया है। यह बदलाव केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है, बल्कि उन कहानियों का भी है जो अब समाज के सामने आ रही हैं।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियाँ इस बदलाव का सबसे प्रेरक उदाहरण हैं। कुछ दशक पहले तक वैज्ञानिक संस्थानों में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। 1950 और 1960 के दशक में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दस प्रतिशत से भी कम था। लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है। अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया में कई भारतीय महिलाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसरो के मंगलयान मिशन में वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ और रितु करिधल जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। टेसी थॉमस को भारत के मिसाइल कार्यक्रम में उनके योगदान के कारण ÷मिसाइल वुमन÷ कहा जाता है। जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किरण मजूमदार-शॉ ने उद्योग और विज्ञान के बीच एक नया पुल बनाया। इससे पहले भी भारत में वैज्ञानिक परंपरा में महिलाओं का योगदान रहा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अन्ना मणि ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। विज्ञान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दिखाती है कि शिक्षा और अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती।

खेल के मैदान में महिलाओं की सफलता ने समाज की सोच को शायद सबसे तेज़ी से बदला है। कभी ऐसा माना जाता था कि खेल पुरुषों का क्षेत्र है, लेकिन आज भारतीय महिला खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। पी.टी. उषा ने 1980 के दशक में भारतीय एथलेटिक्स को नई पहचान दी। बाद में साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु ने बैडमिंटन में विश्व स्तर पर भारत की उपस्थिति मजबूत की। मुक्केबाज़ी में एम.सी. मैरी कॉम ने छह बार विश्व चैंपियन बनकर यह साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं। कुश्ती में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने पारंपरिक सामाजिक ढाँचों को चुनौती दी। क्रिकेट में मिताली राज और हरमनप्रीत कौर जैसी खिलाड़ियों ने महिला क्रिकेट को नई लोकप्रियता दिलाई। खेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में महिला खिलाड़ियों को मिलने वाली सरकारी सहायता और प्रशिक्षण सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी और सफलता दोनों बढ़ी हैं।

स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में मेडिकल शिक्षा के शुरुआती दौर में महिला डॉक्टरों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। भारत की पहली महिला डॉक्टरों में आनंदीबाई जोशी का नाम इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने उन्नीसवीं सदी में ही चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी थी। बाद में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने न केवल चिकित्सा सेवा दी बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया। आज देशभर में लाखों महिला डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यह साफ दिखाई दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आशा कार्यकर्ताओं और नर्सों ने दूर-दराज़ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इन सब क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानियाँ नहीं हैं। यह सामाजिक परिवर्तन का संकेत हैं। शिक्षा के प्रसार, तकनीक के विस्तार और कानूनी सुधारों ने महिलाओं को नए अवसर दिए हैं, लेकिन असली बदलाव तब आया जब महिलाओं ने खुद अपने अधिकारों और संभावनाओं को पहचाना। पिछले तीन दशकों में महिला साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1991 की जनगणना में महिला साक्षरता दर लगभग 39 प्रतिशत थी, जो 2011 तक बढ़कर 65 प्रतिशत से अधिक हो गई। शिक्षा ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में अधिक भागीदारी का अवसर दिया है।आज जब हम समाज में हो रहे बदलाव को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने अपनी दुनिया केवल बदली ही नहीं, बल्कि उसे नए अर्थ भी दिए हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है जब समाज का हर वर्ग उसमें सक्रिय रूप से भाग ले। राजनीति में नेतृत्व, विज्ञान में शोध, कला में रचनात्मकता और खेल में संघर्ष—इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति ने समाज को अधिक संतुलित और संवेदनशील बनाया है। महिलाओं ने यह इंतजार नहीं किया कि कोई और उनके लिए रास्ता बनाए। उन्होंने खुद रास्ते बनाए, अपने कदमों से उन्हें मजबूत किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावनाएँ छोड़ीं। यही कारण है कि आज का भारत जब अपनी प्रगति की कहानी लिखता है, तो उसमें महिलाओं के संघर्ष, साहस और उपलब्धियों का अध्याय सबसे प्रेरक दिखाई देता है।

मंत्री श्री सारंग ने नरेला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिये निर्देश

शासकीय भूमि से अवैध कब्जे, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानें हटाने के निर्देश

भोपाल। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 69, 70 और 71 का दौरा कर शासकीय भूमि से अवैध कब्जे, मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानें हटाने के निर्देश दिए। क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मंत्री श्री सारंग स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सारंग ने शासकीय भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नगर निगम, राजस्व, पुलिस सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध अतिक्रमण पर बने स्थानों को पेयजल, विद्युत सहित किसी भी प्रकार के शासकीय कनेक्शन न दिए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि यदि ऐसे स्थानों को पहले से कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए तथा यह जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से यह कनेक्शन दिए गए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री श्री सारंग ने गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और शहंशाह गार्डन, अशोका गार्डन क्षेत्र में पहुंचकर शासकीय भूमि की स्थिति का निरीक्षण किया और स्थानीय रहवासियों से भी चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किए गए हैं और कुछ जगहों पर बिना अनुमति के गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस पर मंत्री श्री सारंग ने मौके पर मौजूद नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी अतिक्रमणों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि शासकीय भूमि

जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसे, फैक्ट्री और मांस की दुकानों की विस्तृत जांच कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन कर शासकीय भूमि पर कब्जा किया है तो उसे तत्काल हटाया जाए और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में शासकीय भूमि का सर्वे कर विस्तृत सूची तैयार की जाए और जहां-जहां अतिक्रमण पाया जाए वहां चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उसे हटाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा न कर सके।

मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने मंत्री श्री सारंग को कई स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की जानकारी दी। मंत्री श्री सारंग ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा और शासकीय भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा क्षेत्र के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अतिक्रमण या शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ जिला कांग्रेस भोपाल शहर का अनोखा प्रदर्शन

पीएम मोदी को दी 'डॉक्टर' की उपाधि

भोपाल। घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर द्वारा आज रोशनपुरा चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना (अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर) के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से 'डॉक्टर' की उपाधि देते हुए विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई का 'डोज' देकर आम जनता को परेशान कर रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'महंगाई का इंजेक्शन' लिखे पोस्टर और तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन में शामिल महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि घर की शुरुआत चूल्हे से होती है और गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। रसोई गैस आम परिवार की मूल आवश्यकता है, लेकिन इसकी कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से गृहिणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कहा कि वर्ष 2014 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ?400 के आसपास थी, जो अब बढ़कर करीब ?920 तक पहुंच गई है। हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगभग ?60 तथा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब ?115 की वृद्धि की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर ने चेतावनी दी है कि यदि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जनहित में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

इस अवसर पर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा युवा कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष भोपाल अभिषेक शर्मा प्रदेश सचिव राजकुमार सिंह महिला कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया समस्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गण पदाधिकारी गण, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायसेन के किले में अवैध हथियार बनाने पर सख्ती

कानूनगो का ट्वीट, महादेव मंदिर में पूजा करने से रोकने वालों को इस पर एक्शन लेना चाहिए

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रायसेन के पुरात्तव विभाग के अधीन किले में अवैध हथियार बनाने, गोला बारूद चलाने, दहशत फैलाने, नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने और पुरातत्व धरोहर को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस देने का फैसला किया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि यहीं स्थित महादेव मंदिर में हिंदुओं को दर्शन करने से रोकने वाले स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन अफसरों को इस मामले में जिम्मेदारों पर मुकदमा बना लेना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है, इसलिए आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। आयोग के सदस्य कानूनगो ने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि मध्यप्रदेश के रायसेन में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किले की सफील से आवासीय बस्ती के ऊपर देसी अवैध तोप चलाकर जनजीवन को खतरे में डाल रहे यह शोहदे ईरान और रमजान के नाम पर भय फैला रहे हैं। यहीं स्थित महादेव के मंदिर में हिंदुओं को दर्शन करने से बड़ी मुस्तैदी से रोकने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा स्थानीय प्रशासन के अफसरों को उतनी ही तत्परता के साथ इन लफंगों पर मुकदमा करना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य कानूनगो ने लिखा है कि बाकी हम तो कार्रवाई के लिए नोटिस भेज ही रहे हैं तब अफसरों को कर्तव्य पालन न करने का हिसाब भी देना होगा। उन्होंने एक्स पर वह वीडियो भी अपलोड किया है जिसके मामले में कार्यवाही नहीं की गई है। कानूनगो ने यह भी लिखा है कि नौकरी सरकार की है और नियम भी सरकार के हैं इसलिए पालन करवाना होगा। उन्होंने कहा है कि इन शोहदों ने इंस्टाग्राम पोस्ट में पुराने वीडियो भी सम्मिलित किए हैं जो एफआईआर लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए।

मौत को मात देकर आई नन्हीं परी

खरगोन में 20 फीट गहरी पुलिया से गिरी गर्भवती महिला, कुछ ही देर बाद गूंजी किलकारी

खरगोन (नप्र)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र के सिरवेल गांव के पास शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में पुलिया से करीब 20 फीट नीचे गिरी गर्भवती महिला को राहगीरों ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। समय पर मिली मदद से महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं।

अज्ञात बाइक सवार ने मारी टक्कर- जानकारी के अनुसार मोहराडी निवासी हीरालाल अपनी गर्भवती पत्नी और भाभी को मोटरसाइकिल से सिरवेल अस्पताल लेकर जा रहा था। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सिरवेल में झूले के पास बनी पुलिया पर सामने से आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सवार बाइक सहित पुलिया से नीचे जा गिरे।

ग्रामीणों की सहायता से पहुंचाया अस्पताल- हादसे में मोटरसाइकिल पुलिया के नीचे चट्टानों पर जा गिरी, जबकि तीनों लोग पानी भरे गड्ढे में गिर पड़े। घटनास्थल पर चारों ओर पत्थर और नुकीली चट्टानें होने के बावजूद तीनों की जान बच गई और उन्हें गंभीर चोट भी नहीं आई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सिरवेल निवासी समाजसेवी विक्रम ठाकुर और रमेश सोलंकी ने हादसे को देखा और तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। उन्होंने ग्रामीणों की सहायता से गर्भवती महिला को पुलिया के नीचे से ऊपर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद उमरिया पंचायत सचिव प्रवीण जायसवाल को मोबाइल पर घटना की जानकारी दी गई।

अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म- सूचना मिलते ही प्रवीण जायसवाल ग्रामीण बाठिया कनासे के साथ चारपहिया वाहन से मौके पर पहुंचे। सभी की मदद से घायल दंपती और उनकी भाभी को सिरवेल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ ही समय बाद गर्भवती महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्राथमिक उपचार के बाद मां और नवजात को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर मिली मदद से महिला और उसके बच्चे की जान बच सकी।

लाड़ली बहना योजना ने बदली मंजू यादव की जिंदगी, सिलाई सेंटर खोलकर बनीं आत्मनिर्भर

● योजना से मिली सहायता से शुरू किया सिलाई का काम ● सिलाई केन्द्र में अन्य महिलाओं को भी दे रहीं रोजगार

भोपाल । कभी सीमित आय और जिम्मेदारियों के बीच अपने परिवार का सहारा बनने का सपना देखने वाली नर्मदापुरम की श्रीमती मंजू यादव आज आत्मनिर्भरता की नई पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से मिली आर्थिक सहायता ने न केवल उनके

जीवन में उम्मीद की नई किरण जगाई, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया।

नर्मदापुरम जिले के वार्ड क्रमांक 31 दीवान चौक ग्वालटोली निवासी 30 वर्षीय श्रीमती मंजू यादव को जून 2023 से योजना के अंतर्गत नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस राशि का उन्होंने सोच-समझकर उपयोग किया और अपने घर से सिलाई का छोटा-सा काम शुरू किया। मेहनत और लगन से शुरू किया गया यह प्रयास धीरे-धीरे एक सफल व्यवसाय में बदलने लगा। फरवरी 2026 तक उन्हें योजना की 33वीं किश्त सहित कुल 43 हजार 500 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। इस आर्थिक सहयोग और सिलाई कार्य से हुए मुनाफे का सदुपयोग करते हुए उन्होंने अपने काम का विस्तार किया और एक सिलाई सेंटर शुरू कर दिया, जिसमें अब पांच सिलाई मशीनें संचालित हो रही हैं। आज मंजू यादव न केवल स्वयं नियमित आय अर्जित कर रही हैं, बल्कि अपने सिलाई सेंटर के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान कर रही हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और आत्मनिर्भरता की नई राह खुली है। श्रीमती मंजू यादव भावुक होकर कहती हैं कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ने उनके जीवन में नया विश्वास जगाया है। इस योजना ने उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया और आज वे गर्व के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान दे रही हैं।

खाना परोस रहे होटल मालिक को साइलेंट अटैक

नर्मदापुरम में थाली में सब्जी रखते-रखते गिरा; भाई ने सीपीआर दिया, नहीं बची जान

नर्मदापुरम (नप्र)। नर्मदापुरम के ग्वालटोली रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में गुरुवार रात एक व्यक्ति की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वह होटल में ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। अचानक वह थाली में सब्जी रखते-रखते नीचे गिर पड़े।

घटना का सीसीटीवी वीडियो शनिवार सुबह सामने आया। मृतक की पहचान अशोक नवलानी (60), निवासी सिंधी कॉलोनी गोकुलपुरी के रूप में हुई है। वह अपने भाई पप्पन नवलानी के साथ मिलकर होटल चलाता था।

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही अशोक नवलानी नीचे गिरे, पहले तो आसपास मौजूद लोगों को समझ नहीं आया। कुछ ही पल बाद होटल के कर्मचारी और उनके भाई पप्पन नवलानी उन्हें उठाने के लिए दौड़े।

खंडवा के पुनासा में 90 वर्षीय बजुर्ग से खेत में गैंगरेप

कुएं में फेंकने का प्रयास किया, 12 घंटे तड़पती रही

खंडवा (नप्र)। जिले के पुनासा क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां खेत में अकेली रहने वाली 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ चार नकाबपोश बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। आरोपियों ने वृद्धा के मुंह में कपड़ा ठूंसकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसका गुप्तांग फट गया और वह खून से लथपथ हालत में करीब 12 घंटे तक खेत में तड़पती रही। घटना के बाद आरोपी उसे कुएं में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसपास खेतों में लोगों की आवाजाही देखकर बदमाश उसे खेत में ही पटककर फरार हो गए।

खेत में अकेली रहती थी बुजुर्ग महिला- नर्मदानगर थाना प्रभारी विकास खींची ने बताया की पीड़ित बुजुर्ग महिला का खेत में ही एक छोटा सा घर है, जहां वह अकेली रहती है। महिला ने बताया कि गुरुवार रात खाना खाने के बाद वह सो गई थी। देर रात चार नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए। आरोपियों ने पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह शोर न मचा सके।

'न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी'

अदालत ने चेक अनादरित मामले में दोषी को सजा-मय ब्याज राशि भुगतान का दंडादेश पारित किया

सोहागपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेजदीपसिंह की अदालत ने वर्ष 2023 में भारतीय स्टेट बैंक एक व्यक्ति को लोन देने के बदले दिए गए चेक के अनादरित होने के मामले में आरोपी के विरुद्ध सजा मय ब्याज राशि भुगतान के दंडादेश का आदेश दिया है। इस मामले में बैंक पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता जयप्रकाश माहेश्वरी, वकील सतीश नामदेव एवं वकील संदीप रघुवंशी ने इस प्रतिनिधि को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिपरिया रोड सोहागपुर में मेसर्स भाई वेल्डिंग वर्कशॉप के प्रोपराइटर इमरान खान पुत्र अयूब खान ने सीसी लिमिट लोन का आवेदन दिया था। जिसमें बैंक की शर्तों के अनुसार सात लाख रुपए का ऋण 17 मार्च 2023 को परिवादी बैंक ने स्वीकृत किया था। जिसमें आरोपी को ऋण राशि नियमित समयानुसार अदा करनी थी। लेकिन आरोपी ने बैंक से प्राप्त ऋण की प्रारंभ से ही समय पर अदायगी नहीं की। इस कारण आरोपी से परिवादी बैंक को सात लाख 30 हजार 911 रुपए एवं ब्याज लेना बाकी निकलता है। बैंक ने ऋण अदायगी के लिए परिवादी बैंक ने आरोपी से बार-बार निवेदन किया। इसके उपरांत आरोपी ने परिवादी बैंक को 24 नवंबर 2023 को केनरा बैंक सोहागपुर में स्वयं के खाते का 7 लाख 30 हजार 911 का एक चेक दिया। उक्त चेक परिवादी बैंक भारतीय स्टेट बैंक सोहागपुर में 28 सितंबर 2023 को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। परिवादी बैंक प्रबंधक को 30 नवंबर 2023 को ज्ञात हुआ ।कि आरोपी के खाते में उक्त चेक राशि भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। इसके

बावजूद जानबूझकर एवं बेईमानी पूर्वक परिवादी को धोखा देते हुए उक्त चेक आरोपी द्वारा प्रदान किया गया था। बैंक के अधिवक्ता जयप्रकाश माहेश्वरी ने कहा कि अभियुक्त का यह कार्य पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय श्रेणी में आता है। परिवादी बैंक ने 'आरोपी को 11 दिसंबर 2023 को पंजीकृत डाक से अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा था।जो 12 दिसंबर 2023 को आरोपी को प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने 15 दिवस के अंदर परिवादी को चेक में वर्णित राशि अर्थात सात लाख 30 हजार 911 रुपये का भुगतान नहीं किया। इसके बाद शाखा प्रबंधक राघवेंद्र राजपूत ने तय समय सीमा में परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिसमें विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेजदीपसिंह ने अभियुक्त इमरान खान आत्मज अयूब खान निवासी किलापुरा वार्ड सोहागपुर को पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत सजा सुनाई है। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय ने छह माह के साधारण कारावास का दंडादेश एवं चेक की राशि सात लाख 30 हजार 911 रुपये पर एक लाख 49 हजार 106 रुपये ब्याज की राशि चुकाने का भी दंड सुनाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त को परिवादी बैंक को आठ लाख 80 हजार 17 रुपये चुकाने होंगे। दंडादेश अनुसार अभियुक्त द्वारा यदि प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है ।ऐसी परिस्थिति में एक माह का साधारण कारावास भी भुगतना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त को अभिरक्षा में लेते हुए सजा वारंट बनाकर पिपरिया उपजेल भेजने के निर्देश दिए हैं।

लौट रहे हैं अमिताभ महानायक का ऐलान

'कौन बनेगा करोड़पति' परदे पर वापस लौट रहा है। ये अचरज वाली बात इसलिए कही जा सकती है, कि जिस शो का अंत आशंका के साथ होता था, कि अगले सीजन में बतौर सूत्रधार अमिताभ लौटेंगे या नहीं! वही सीजन इस बार अपेक्षाकृत जल्दी शुरू होने की संभावना है। क्योंकि, इस शो की कल्पना अमिताभ बच्चन के बगैर नहीं की जा सकती। एक बार नए सूत्रधार का प्रयोग जरूर करने की कोशिश की गई, पर वो सफल नहीं हुआ।

महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर ज्ञान मंच पर कंटेस्टेंट की किस्मत संवारते नजर आएंगे। क्योंकि, टेलीविजन जगत का सबसे बड़ा रियलिटी शो अपनी अगली पारी के लिए तैयार है। 'देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं।' यह आवाज जल्द ही आपके घरों में फिर से गूंजने वाली है। देश के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। सोनी टीवी के इस शो का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर आ चुका है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने पुराने अंदाज में शो की वापसी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं।

प्रोमो की शुरुआत भी बेहद दिलचस्प अंदाज से होती है। अमिताभ बच्चन के मजेदार अंदाज में. कैमरा के सामने आकर कहते हैं 'सरप्राइज!' लाल रंग के वेलवेट कोट और ब्लैक ट्राउजर में वो हमेशा की तरह बेहद शानदार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वे आईने के सामने खड़े होकर 'सरप्राइज' कहते हुए अपनी बाहें फैलाते हैं। हालांकि, बीच में वे अपनी एक छोटी सी गलती पर मुस्कुराते हुए 'सॉरी, गड़बड़ हो गई' भी कहते हैं और फिर अपना वीडियो आगे बढ़ाते हुए केबीसी के रजिस्ट्रेशन का ऐलान करते हैं।

केबीसी के 18वें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रजिस्ट्रेशन की तारीख। वीडियो में साफ तौर पर बताया गया है कि 9 मार्च से शो के सवाल और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दर्शक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव ऐप के माध्यम से इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोमो के अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर भी दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों को आगाह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या लॉटरी के झांसे में न आएं। चैनल ने स्पष्ट किया है कि 'कौन बनेगा करोड़पति' कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क की मांग नहीं करता है।

अमिताभ बच्चन और केबीसी का नाता सालों पुराना है। पिछले सीजन के अंत में जब अमिताभ भावुक हुए थे। तब कई कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो वापस आएंगे। लेकिन, अब इस आधिकारिक प्रोमो ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। फैंस अपने चहेते होस्ट को फिर से हॉट सीट के सामने देखने के लिए बेताब हैं। जानकारी के मुताबिक ये नया सीजन जुलाई या अगस्त तक ऑन एयर होगा।

टिटहरी गीत पर बवाल बादशाह को नोटिस

मशहूर गायक और रैपर बादशाह एक बार फिर विवादों में आ गए। उनके नए हरियाणवी गीत 'टिटहरी' को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्हें समन भेजा है। आयोग ने गायक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में जारी हुए इस गीत के कुछ बोलों और दृश्य को लेकर आपत्ति जताई गई है। आयोग का कहना है कि इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचती है।

6 मार्च को जारी समन में बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, को इस मामले में मुख्य पक्षकार बताया गया है। यह समन पानीपत के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जारी किया गया है। आयोग ने सुनवाई की तिथि 13 मार्च 2026 सुबह 11:30 बजे तय की है, जो पानीपत के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में होगी।

गीत के बोलों के अलावा उसके दृश्य को लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई है। वीडियो में स्कूल की वर्दी पहनी बच्चियों को दिखाए जाने पर आयोग ने सवाल उठाए हैं। आयोग का कहना है कि हरियाणवी संस्कृति और समाज से जुड़े गीतों में इस तरह की आपत्तिजनक भाषा और दृश्य नहीं होने चाहिए।

'ओह माय गॉड 3' से अलग हुई रानी मुखर्जी

अभिनेत्री रानी मुखर्जी और अभिनेता अक्षय कुमार को एक साथ फिल्म 'ओ माय गॉड 3' में देखने की चर्चा थी। लेकिन, अब खबर है कि रानी मुखर्जी इस परियोजना का हिस्सा नहीं रहेंगी। फिल्म में रानी मुखर्जी को मुख्य खलनायिका की भूमिका के लिए चुना गया था। जबकि, अक्षय कुमार इसमें पहले की तरह संक्षिप्त भूमिका में दिखाई देने वाले थे। अभिनेत्री को कहानी पसंद भी आई थी और आगे बातचीत होनी थी, लेकिन यह योजना प्रारंभिक चरण में ही रुक गई।

सूत्रों के मुताबिक अक्षय और रानी के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध हैं और दोनों साथ काम करने को लेकर उत्साहित भी थे। अब रानी के अलग होने के बाद निर्माता इस भूमिका के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इसी वर्ष मई और जून में शुरू हो सकती है। रानी मुखर्जी हाल ही में फिल्म 'मर्दानी 3' में दिखाई दी थीं। इस फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया था और इसके निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं। फिल्म को प्रदर्शित होने के पहले दिन लगभग 4 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी।

रियल बॉक्स

फिर लौट आया सिनेमा का स्वर्णिम युग!

हेमंत पाल

लेखक 'सुबह सवेरे' इंदौर के स्थानीय संपादक है।

साल यानी 2025 में भारतीय फिल्मों का कुल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13,395 करोड़ रुपए तक पहुंचना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आंकड़ा महामारी से पहले के तीन वर्षों के औसत से 32% अधिक है, जो दर्शकों के व्यवहार में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। लंबे समय तक घरों में बंद रहने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने के बाद जब दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों में लौटने का अवसर मिला, तो उन्होंने इसे बड़े उत्साह के साथ अपनाया। तीसरी तिमाही में 4.05 करोड़ दर्शकों का सिनेमाघरों में पहुंचना और पिछले वर्ष की समान अवधि से 8.6% की वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि थिएटर अब केवल मनोरंजन का विकल्प नहीं बल्कि सामाजिक अनुभव का केंद्र बन चुके हैं। इस सफलता के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण मजबूत कंटेंट पाइपलाइन है। वर्ष 2025 में 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाली 37 फिल्मों का रिकॉर्ड बनना यह दर्शाता है कि निर्माताओं ने दर्शकों की पसंद को समझते हुए विविध विषयों पर फिल्में बनाई हैं। बड़े बजट की व्यावसायिक फिल्मों से लेकर छोटे बजट की कंटेंट-आधारित फिल्मों तक, दर्शकों को हर शैली और भाषा में विकल्प मिले। इससे सिनेमाघरों में लगातार भीड़ बनी रही और उद्योग को स्थिरता मिली।

मल्टीप्लेक्स उद्योग, विशेषकर पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनियों ने इस उछाल का भरपूर लाभ उठाया है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 166.5% बढ़कर 95.7 करोड़ रुपए तक पहुंचना केवल वित्तीय सफलता नहीं बल्कि पूरे प्रदर्शन तंत्र की मजबूती का संकेत है। कंपनी की कुल आय में 9% की वृद्धि और 1,919.6 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताता है कि सिनेमाघर केवल टिकट बिक्री पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि फूड एंड बेवरेज, प्रीमियम अनुभव और ब्रांड साझेदारियों के जरिए भी राजस्व बढ़ा रहे हैं। औसत टिकट की कीमत का 293 रुपए तक पहुंचना और प्रति व्यक्ति खान-पान खर्च का 146 रुपए तक बढ़ना दर्शकों की खर्च करने की क्षमता और उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आज का दर्शक केवल फिल्म देखने नहीं, बल्कि एक पूरे अनुभव के लिए सिनेमाघर जाता है। बेहतर स्क्रीन, उन्नत ध्वनि तकनीक, आरामदायक सीटें और विविध खान-पान विकल्प उसके लिए महत्वपूर्ण हो गए। यही कारण है कि टिकट की कीमत में वृद्धि के बावजूद दर्शकों की संख्या में गिरावट नहीं आई, बल्कि वृद्धि दर्ज की गई है।

पीवीआर आईनॉक्स की रणनीति में छोटे शहरों और नए क्षेत्रों में विस्तार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 112 शहरों में 1,791 स्क्रीन का नेटवर्क यह दिखाता है कि सिनेमाघर अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहे। टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्क्रीन जोड़ने से नए दर्शक वर्ग तक पहुंच संभव हुई है। लेह और गंगटोक जैसे क्षेत्रों में विस्तार इस बात का संकेत है कि सिनेमा अब देश के हर कोने तक पहुंचने की क्षमता रखता है। दक्षिण भारत में 33% स्क्रीन का होना और उत्तर भारत में 27% स्क्रीन का वितरण क्षेत्रीय संतुलन को दर्शाता है। इस विस्तार का आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट है। मूवी एग्जीबिशन सेगमेंट से कमाई का चार गुना बढ़कर 159.3 करोड़ रुपए तक पहुंचना बताता है कि स्क्रीन बढ़ाने की रणनीति सफल रही है। साथ ही, वित्त लागत में 22.2 करोड़ रुपए की कमी और 27.1 करोड़ रुपए के टैक्स क्रेडिट ने कंपनी की लाभप्रदता को मजबूत किया है। यह संकेत देता है कि मल्टीप्लेक्स उद्योग अब केवल विस्तार नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थिरता पर भी ध्यान दे रहा है। क्षेत्रीय सिनेमा की भूमिका इस स्वर्णिम दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2025 में क्षेत्रीय फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6,488 करोड़ रुपए तक पहुंचना बताता है कि भारतीय दर्शक अब केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। मलयालम फिल्मों का लगातार दूसरे वर्ष 1,000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करना यह दिखाता है कि क्षेत्रीय उद्योग गुणवत्ता और कहानी कहने के स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कन्नड़ सिनेमा की 74% और गुजराती सिनेमा की 188% वृद्धि यह साबित करती है कि स्थानीय कहानियां और सांस्कृतिक जुड़ाव दर्शकों को आकर्षित करने में अत्यंत प्रभावी हैं।

भारतीय सिनेमा के लिए साल 2025 सही मायनों में यादगार रहा। इस साल महामारी के बाद गुम हुई सिनेमा संस्कृति पूरी तरह लौट आई और बड़े बजट, दमदार कंटेंट व पैन-इंडिया अपील ने

बॉक्स ऑफिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साल के शुरू में 'छावा' ने दर्शकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो साल के अंत में 'धुरंधर' की धमक ने दर्शकों को चमत्कृत कर दिया। इन एक्शन वाली फिल्मों से लगा कि दर्शक को ऐसी फ़िल्में ज्यादा पसंद आ रही है, तो यह भ्रम 'सैयारा' ने तोड़ दिया। इस प्रेम कहानी ने दर्शकों को मोहब्बत से सराबोर किया और आंखें भी गीली की। इस साल 'स्त्री-2' ऐसी फिल्म रही, जिसने कंटेंट की ताकत साबित की। हॉरर-कॉमेडी के सफल फॉर्मूले, मजबूत स्क्रिप्ट और राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर की जोड़ी ने दर्शकों को आकर्षित किया। छोटे बजट में बड़े मुनाफे ने इसे ट्रेड की पसंदीदा फिल्म बनाया। 'पुष्पा-2' ने भी कमाई का सिलसिला जारी रखा। अल्लू अर्जुन के स्टारडम, सशक्त एक्शन और बड़े पैमाने पर रिलीज रणनीति ने इसे सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल किया। एंटरटेनमेंट और यादगार डायलॉग इसकी ताकत बने। विजुअल ग्रैंड्योर और पौराणिक-साइंस फिक्शन मिश्रण से दर्शकों को 'कल्कि 2898 एड़ी' ने सिनेमाघरों तक खींचा। प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की मौजूदगी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक इसकी सफलता का आधार रही। इसके अलावा 'भूल भुलैया-3' जैसी कुछ मध्यम बजट की सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। क्योंकि, दर्शक अब कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बावजूद सिनेमाघरों की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि बड़े पर्दे का अनुभव अब भी अद्वितीय है। बड़े बजट की फिल्मों के दृश्य प्रभाव, ध्वनि और सामूहिक दर्शक प्रतिक्रिया को घर पर दोहराना कठिन है। इसके अलावा, मल्टीप्लेक्स कंपनियों ने प्रीमियम फॉर्मेट्स, विशेष स्क्रीनिंग और तकनीकी नवाचारों के जरिए सिनेमाघरों को आधुनिक बना दिया है। इससे युवा दर्शकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। हालांकि, इस चमकदार तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। टिकट कीमतों में लगातार वृद्धि भविष्य में मध्यम वर्ग और छोटे शहरों के दर्शकों पर प्रभाव डाल सकती है। यदि कीमत बहुत अधिक बढ़ती हैं तो दर्शक फिर से डिजिटल विकल्पों की ओर झुक सकते हैं। इसके अलावा, कंटेंट की गुणवत्ता बनाए रखना भी उद्योग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दर्शक अब पहले से अधिक जागरूक और चयनात्मक हो चुके हैं। फिर भी, वर्तमान आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारतीय सिनेमा उद्योग ने महामारी के बाद न केवल खुद को पुनर्जीवित किया है बल्कि नए विकास मॉडल भी विकसित किए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का उदय, मल्टीप्लेक्स का विस्तार, प्रीमियम अनुभवों की मांग और विविध कंटेंट की उपलब्धता मिलकर एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। निर्माता, वितरक और प्रदर्शक सभी अब डेटा-आधारित निर्णयों और दर्शक-केंद्रित रणनीतियों पर ध्यान दे रहे हैं।

भविष्य की दृष्टि से देखें तो उद्योग के सामने अपार संभावनाएं हैं। भारत की युवा आबादी, बढ़ती आय और शहरीकरण की प्रक्रिया सिनेमा के लिए दीर्घकालिक बाजार तैयार कर रही है। यदि कंपनियां छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और सुलभ सिनेमाघर मॉडल विकसित करती हैं, तो दर्शकों का आधार और भी व्यापक हो सकता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता विदेशी राजस्व के नए अवसर खोल रही है। अंततः, वर्ष 2025 भारतीय सिनेमा के लिए केवल आर्थिक सफलता का वर्ष नहीं बल्कि आत्मविश्वास की वापसी का प्रतीक है। दर्शकों ने यह साबित कर दिया है कि सिनेमा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मजबूत कंटेंट, तकनीकी नवाचार और व्यापक विस्तार की रणनीतियों ने उद्योग को एक नए युग में प्रवेश कराया है। यदि यह गति बरकरार रहती है और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा न केवल घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक मंच पर भी और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान दौर को सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जा रहा है, एक ऐसा समय जब परंपरा और आधुनिकता मिलकर मनोरंजन की दुनिया को नई दिशा दे रहे हैं।

- hemantpal60@gmail.com/ 9755499919

महिला दिवस विशेष

बिन नारी बेरंग है सिनेमा का रंग बिरंगा परदा

अशोक जोशी

आज की तरह हर साल महिला दिवस पर महिलाओं पर चर्चा होती है। लेकिन, फिल्मों में महिलाओं के योगदान पर ज्यादा बात नहीं होती। जबकि, हकीकत यह है कि हिंदी सिनेमा की विकास यात्रा में नारियों को उल्लेखनीय योगदान रहा है। नारी, सिनेमा का सबसे अनिवार्य और सशक्त घटक है। नारी के बिना सिनेमा भाव विहीन नजर आता है। जिन दिनों

सिनेमा का प्रादुर्भाव हुआ, सिनेमा में महिलाओं का काम करना प्रतिबंधित था। लेकिन, तब भी सिनेमा का परदा नारी विहीन नहीं हुआ। तब पुरुष कलाकार ही नारी का स्वांग रचकर दर्शकों को गुदगुदाया करते थे। लेकिन, जब परदे पर नायिकाओं का पर्दापण हुआ, नारी चरित्र सिनेमा में सशक्त आकार लेने लगे। आज जब सिनेमा सवा सौ साल से ज्यादा का सफर तय कर चुका है, नारी पात्र भारतीय सिनेमा की आत्मा बनकर उसमें समा गए हैं।

हिंदी सिनेमा मे वी शांताराम नारी समस्या को परदे पर सशक्त तरीके से उठाने वाले एक सशक्त फ़िल्मकार थे। उन्होंने प्रभात और राजकमल फिल्म निर्माण संस्थाओं के माध्यम से एक से एक बेजोड़ समाज सुधार की कलात्मक फिल्में बनाकर भारतीय सिनेमा मे नारियों के महत्व को प्रतिपादित किया। उनकी फिल्मों में 1937 में प्रदर्शित दुनिया न माने उल्लेखनीय है। बेमेल विवाह की समस्या पर आधारित यह फिल्म स्त्रीत्व की गरिमा को बेहद खूबसूरती से उभारती है। शांता आप्टे ने नायिका नीरा की भूमिका में प्राण फूंक दिए थे। नारी को को भोग्या, चरणों की दासी और उपभोक्ता-वस्तु मानने वालों को यह फिल्म करारा सबक सिखाती है। आज की इक्कीसवीं सदी की फिल्मों में भी यह जज्बा दिखाई नहीं देता।

1936 में निर्मित 'अछूत कन्या' ब्राह्मण लड़के और अछूत लड़की की एक दारुण प्रेम कहानी है। यह एक दुखांत फिल्म है। इस वर्जित और उपेक्षित विषय को पहली बार फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच लाने का साहसिक प्रयास किया था। इससे मिलते जुलते विषय पर 1959 में विमल राय ने 'सुजाता' बनाई, जो फिर से अछूत लड़की और ब्राह्मण लड़के के प्रेम की कहानी है। विमल राय की यह फिल्म आज़ादी के बाद इस विषय पर बनाई गई पहली फिल्म थी। 'सुजाता' और उसके बाद हमारे देश में बहुत ही सशक्त सामाजिक सरोकार की फिल्में बनी, फिर भी हमारे यहां आज भी अंतर्जातीय और विधवा विवाह पूरी तरह मान्य नहीं हैं। राजकपूर और मीना कुमारी की ख्वाजा अब्बास निर्देशित फिल्म 'चार दिल चार राहें' भी इसी तरह समाज में नारियों की उपेक्षा की कहानी कहती है।

फिल्मों में नारी की स्थिति का चित्रण करने में बीआर चोपड़ा का उल्लेखनीय योगदान रहा। विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने 1958 में 'एक ही रास्ता' का निर्माण किया। उन्होंने साहस के साथ फिल्म में विधवा स्त्री का विवाह करवाकर सुधार की एक नई परंपरा को स्थापित किया था। अगले ही साल उन्होंने अविवाहित मातृत्व की समस्या से जूझने वाली स्त्रियों के जीवन के बिखराव और उसकी परिणति को दर्शाने वाली सशक्त फिल्म 'धूल का फूल' का निर्माण किया। ये फिल्में समाज को ऐसी विषम स्थितियों से बचने के लिए आगाह करती हैं और उन स्थितियों को बेबाकी से प्रस्तुत कर स्त्रियों के पक्ष में समाज को खड़े होने का साहस प्रदान करती हैं। बीआर चोपड़ा अपनी एक और फिल्म 'इंसाफ का तराजू' में

बलात्कार से पीड़ित लडकी को न्याय दिलाते हैं। इस विषय पर बहुत कम फिल्में बनी, इसलिए इसे एक नई साहसपूर्ण प्रस्तुति के रूप में स्वीकार किया गया। 'निकाह' में उन्होंने तलाक और हलाला जैसे विषयों को छूने का प्रयास किया तो उन्हीं की फिल्म 'साधना' समाज में वेश्याओं की स्थिति पर प्रकाश डालने में सफल रहीं।

अपने शैशव काल से ही हिंदी फिल्में स्त्री प्रधान रहीं हैं। हिंदी फ़िल्मकारों ने भारतीय स्त्री के सभी रूपों को फिल्मों में प्रस्तुत किया है। घरेलू स्त्री, कामकाजी स्त्री, किसान स्त्री, विवाहित और अविवाहित स्त्री आदि। जुझारू स्त्री, संघर्षशील स्त्री और अन्याय और अत्याचार से लड़ने वाली स्त्री आदि रूप हिंदी फिल्मों में प्रमुख रूप से आते रहे हैं। महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'औरत' और उसका संशोधित संस्करण 'मदर इंडिया' भारतीय किसान नारी के संघर्ष और त्रासदी की महागाथा है। जिसमें ग्रामीण महाजनी सभ्यता की क्रूरता और अत्याचार से लड़ती हुई नारी की मार्मिक कहानी भी है। जमींदारी अन्याय से लड़ते लड़ते गांवों में डाकुओं की जमात भी तैयार होती है। ग्रामीण सामंती अत्याचार से उत्पन्न डाकू समस्या को उजागर करने वाली फिल्मों में नारी की विवशता को मुझे जीने दो, गंगा जमुना, जिस देश में गंगा बहती है और शेखर कपूर की 'बैंडिट क्वीन' में पूरी विश्वसनीयता के साथ परदे पर उतारा गया।

राज कपूर द्वारा निर्मित 'प्रेम रोग' में अभिजात्य परिवार की विधवा युवती का विवाह सामान्य वर्ग के युवक से करवाकर सामाजिक विषमता को मिटाने की पहल की गई। 'राम तेरी गंगा मैली' में भी राज कपूर ने नारी व्यथा को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। इसी श्रेणी में राजीव कपूर निर्देशित 'प्रेमग्रंथ' भी आती है जो कि यौन शोषण से उत्पीड़ित नारी को काठ की हांडी के रूप में प्रस्तुत करती है। इस फिल्म के माध्यम से ऐसी लांछित स्त्रियों को समाज में स्वीकार करने की पहल की गई। कुछ इसी तरह की फिल्म थी राज कुमार संतोषी की 'लज्जा' जिसमें समाज के अलग-अलग परिवेशों से आने वाली तीन शोषित स्त्री पात्रों के दारुण शोषण और मुक्ति के संघर्ष को दर्शाया गया है। राजकुमार संतोषी की फिल्म 'दामिनी' में भी बलात्कार से पीड़ित घर की एक नौकरानी को न्याय दिलाने की कहानी को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया था।

श्याम बेनेगल की पहली फिल्म 'अंकुर' भी अछूत औरत और ब्राह्मण आदमी के रिश्ते की कहानी है। इसके बाद, भुवन शोम, मृगया, भूमिका, मंडी, चक्र आदि फिल्मों में श्याम बेनेगल ने हाशिये पर पड़ी नारियों की सामाजिक स्थिति की दर्दमय झांकी प्रस्तुत की। प्रकाश झा भी नारी विषय पर फिल्में बनाने में माहिर है। उनकी फिल्म 'दामुल' में अमीर लोगों द्वारा गरीबों का शोषण दिखाया गया। इसके बाद 'मृत्युदंड' में उन्होंने ग्रामीण वातावरण में स्त्री के यौन शोषण और कर्मकाण्डी धार्मिक व्यवस्था द्वारा स्त्री की दुर्गति के प्रयासों के विरुद्ध स्त्रियों के संघर्ष को दर्शाया गया। यहां 'खून भरी मांग, दीवार और स्मिता पाटिल की 'वारिस' की चर्चा करना भी प्रासंगिक होगा जिसमें महिलाओं की महिमा को शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा क्वीन, गुलाबी गैंग, इंग्लिश-विंग्लिश, पिंक, दंगल, छपाक, थप्पड़, कहानी, मर्दानी, सीता और गीता, लापता लेडीज, दामिनी, गुंजन सक्सेना, नीरजा, और गंगूबाई काठियावाड़ी में भी महिलाओं से संबंधित विषयों को छुआ है।

सिनेमा में नारी व्यथा और उनकी दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली फिल्मों उनके निर्माताओं के योगदान को स्मरण करना महत्वपूर्ण है। उतना ही परदे पर नारी दशा को प्रकट करने वाली अभिनेत्रियों में शांता आप्टे से लेकर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन, वहीदा रहमान, जया बच्चन, हेमा मालिनी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, राखी, रेखा, डिम्पल कपाड़िया, जीनत अमान, माधुरी दीक्षित मीनाक्षी शेषाद्री, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, और आलिया भट्ट सहित सभी नायिकाओं और सहनायिकाओ के योगदान को स्मरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण एक नए मिशन में बदल गया है, जहां प्रदेश की हर महिला प्रगति के पथ पर एक स्वावलंबी भागीदार है

मध्यप्रदेश के प्रगतिशील परिवर्तन की स्वावलंबी भागीदार नारी शक्ति

सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

- 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को हर माह ₹1500 की सहायता से सुनिश्चित हो रहा **आर्थिक स्वावलंबन**
- महिलाओं के नाम संपत्ति पर रजिस्ट्री शुल्क में 2% विशेष रियायत से मिला भूमि और संपत्ति पर अधिकार
- 62 लाख **महिलाएं स्व-सहायता** समूहों से जुड़कर हुईं आत्मनिर्भर
- **'लखपति दीदी योजना'** से 12 लाख+ महिलाओं की वार्षिक आय हुई ₹1 लाख से अधिक
- 89 लाख महिलाओं को **उज्ज्वला** गैस कनेक्शन और लाड़ली बहनों को **₹450 में सस्ते गैस सिलेंडर से मिली** रसोई में राहत
- 'एक बगिया माँ के नाम' अभियान से कृषि में बढ़ रही भागीदारी

प्रशासनिक-राजनीतिक भागीदारी

- शासकीय नौकरियों में **35% तक आरक्षण** से बढ़ी प्रशासनिक एवं निर्णयकारी पदों पर महिलाओं की मौजूदगी
- पंचायत एवं नगरीय निकायों में **50% तक आरक्षण से मिली लोकतंत्र** में ऐतिहासिक भागीदारी

सुरक्षा ने बढ़ाया आत्मविश्वास

- **'वन स्टॉप सेंटर'** से हिंसा पीड़िता को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य और कानूनी परामर्श, हर जिले में सुरक्षित एवं त्वरित सहायता
- थानों में विशेष **महिला हेल्प डेस्क**
- संकट की स्थिति में डायल **181/ 1098** या **112** पर तुरंत सहायता
- छात्राओं एवं कार्यरत महिलाओं के लिए **सुरक्षित और किफायती छात्रावास**

शिक्षा एवं रोज़गार के अवसरों तक पहुंच

- जन्म से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता दे रही **लाड़ली लक्ष्मी योजना**
- जन्मदर सुधार, शिक्षा प्रोत्साहन और बालिकाओं की सुरक्षा पर केंद्रित अभियान **बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ**
- **एमएसएमई** इकाइयों में महिलाओं को प्रोत्साहन, 47% से अधिक एमएसएमई महिलाओं के नेतृत्व में संचालित
  - कौशल, परामर्श और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु **हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन** एकीकृत केंद्र संचालित
  - कौशल और रोज़गार सहायता के लिए **'हम होंगे कामयाब' कार्यक्रम**

स्वास्थ्य की बेहतरी

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** से गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण सहायता
- **जननी सुरक्षा योजना** से ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को सीधी सहायता
- गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए पोषण तथा बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा हेतु **आंगनवाड़ी सेवाएं**
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में जागरुकता हेतु **सुमन सखी चैटबॉट** की शुरुआत

डॉ. मोहन यादव अभ्युदय मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

D11217/25